सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" आनंद से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से आनंद मिलता है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। आनंद अल्प समय के लिए और संतुष्टि जीवन भर के लिए आनंद देती है...!! "

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–192 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 31 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

संसद में संग्राम : खड़गे का अमित शाह पर सीधा हमला, 15 मिनट में पास हुआ 'वंदे मातरम बिल'

राज्यसभा में 'एंटी पेपर लीक बिल' पर खड़गे–नड्डा में तीखी बहस, लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हुआ विधेयक

नई दृष्टिबिंदु / नईदिल्ली

संसद के मानसून सत्र में बुधवार को दोनों सदनों में सियासी घमासान देखने को मिला। एक तरफ राज्यसभा में 'एंटी पेपर लीक बिल' पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ लोकसभा में 'वंदे मातरम बिल' महज 15 मिनट की चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया। उच्च सदन में 'द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल' यानी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान माहौल उस समय गरमा गया जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायरी के साथ सरकार पर निशाना साधा।

खड़गे का सीधा हमला: खड़गे ने कहा – "पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पीटते रहे..."। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के बढ़ते आक्रोश और अपनी कुर्सी बचाने के डर से यह बिल लाया है।

PM और गृह मंत्री पर निशाना: खड़गे ने कहा कि जंतर–मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। "आप बंद कमरे में छुपकर नहीं रह सकते, एक दिन जनशक्ति आपको बाहर खींचकर लाएगी।"

'असंसदीय' शब्द पर हंगामा: खड़गे के इस बयान पर नेता सदन जेपी नड्डा अपनी सीट से उठे और इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की।

आरएसएस–मनुस्मृति का जिक्र: खड़गे द्वारा कुलपतियों और प्रोफेसरों की भर्ती में आरएस के प्रभाव और मनुस्मृति के श्लोकों का जिक्र करने पर सत्ता पक्ष ने 'गुंडागर्दी नहीं चलेगी' के नारे लगाए। जेपी नड्डा और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे के आरोपों को तथ्यों से परे बताया।

लोकसभा: भारी हंगामे के बीच 15 मिनट में पास हुआ 'वंदे मातरम बिल'

लोकसभा में दिन की शुरुआत ही जंतर–मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे से हुई। बार–बार स्थगन के बाद दोपहर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 'वंदे मातरम बिल' सदन में पेश किया।

डीएमके सांसद कनिमोझी और बीजेपी सांसद संबित पात्रा के छोटे–छोटे भाषण और मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया करीब 15 मिनट में पूरी हुई।

संसद परिसर में भी हाई–ड्रामा

सदन के बाहर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

'दानपात्र' प्रदर्शन: सपा और 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर संसद परिसर में दानपात्र रखकर सांकेतिक प्रदर्शन किया।

लाठीचार्ज पर घेराव: प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने "लाठी–गोली की सरकार नहीं चलेगी" और "अमित शाह जवाब दो" के नारे लगाए।

कल्याण बनर्जी vs प्रियंका गांधी: निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी गले में बागी सांसदों के पोस्टर वाला बैनर लटकाकर घूमते दिखे। इस दौरान प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत भी कैमरे में कैद हुई।

कैंटीन की वायरल फोटो: टीएमसी सांसद सौगत रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संसद की कैंटीन में लंच करते हुए तस्वीरें वायरल हुईं, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

संसद के इस सत्र में सरकार ने जहां जरूरी बिलों को तेजी से पारित कराया, वहीं विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। पेपर लीक, लाठीचार्ज और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर आने वाले दिनों में टकराव और तेज होने के संकेत हैं।

राजेश मूणत कथित सेक्स सीडी कांड भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

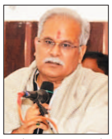

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित राजेश मूणत कथित सेक्स सीडी कांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उड़क की विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश बघेल द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत उनके खिलाफ दोबारा आरोप तय करने के निर्देश दिए गए थे।

क्या है पूरा मामला? 2017 की घटना

यह मामला साल 2017 का है। आरोप है कि तत्कालीन मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत की एक कथित अश्लील मॉर्फ्ड यानी झूठी सीडी तैयार कर उसे सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया गया था, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच पूरी होने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने भूपेश बघेल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के प्रसारण जैसी गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी।

अदालत के फैसलों का अब तक का सफर

मार्च 2025 - डिस्चार्ज आदेश: विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।

जनवरी 2026 - आदेश पलटा: इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले आदेश को पलटते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ दोबारा आरोप तय करने का निर्देश दे दिया।

वर्तमान - हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: विशेष अदालत के इसी निर्देश को भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीबीआई विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई में यह तय होगा कि विशेष अदालत का यह आदेश कानूनी रूप से कितना टिकाऊ है।

हाईकोर्ट में भूपेश बघेल की ओर से दी गई मुख्य दलीलें

अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश: तर्क दिया कि पुनरीक्षण अदालत का काम केवल यह देखना था कि निचली अदालत का डिस्चार्ज आदेश सही था या नहीं। विशेष अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर नए सिरे से आरोपों की प्रकृति को प्रभावित करने वाला निर्देश दिया।

ठोस साक्ष्यों का अभाव: अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है जिसके आधार पर आरोप तय किए जा सकें। केवल सह–आरोपियों के साथ किसी होटल में ठहरने मात्र को आपराधिक साजिश का अकाट्य प्रमाण नहीं माना जा सकता।

जालसाजी या सीडी प्रसार में कोई भूमिका नहीं: याचिका में कहा गया कि भूपेश बघेल की न तो जालसाजी में और न ही कथित सीडी के प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संलिप्तता रही है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सफाई: गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्होंने केवल सह–आरोपी विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उस दौरान किसी आपत्तिजनक सीडी का वितरण किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई में हाईकोर्ट विशेष अदालत के आदेश की वैधानिकता पर विस्तृत सुनवाई करेगा।

बांकीपुर में पीके का दांव vs दतिया में नरोत्तम की साख : 3 अगस्त को तय होगा दो राज्यों के उपचुनाव का भविष्य

बिहार में बीजेपी का 30 साल का किला खतरे में, MP में टिकट कटने से गरमाई बीजेपी की अंदरूनी राजनीति

आलोक तिवारी / पटना-भोपाल

देश की सियासत की नजर अब बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनावों पर टिकी है। दोनों सीटों पर भले ही राज्य सरकारों का अस्तित्व दांव पर न हो, लेकिन नतीजे नेताओं की व्यक्तिगत साख और 2025–2029 के चुनाव चक्र की दिशा तय करेंगे। मतगणना 3 अगस्त को होगी।

जानकारों के अनुसार मुख्य स्थिति

पार्टी	स्थिति	विश्लेषण
बीजेपी	नीरज सिन्हा मामूली आगे	5,000 से 7,000 वोटों की बारीक बढ़त, लेकिन कैडर में सुस्ती
जन सुराज	कांटे की टक्कर	उलटफेर की पूरी संभावना, कार्यकर्ता आक्रामक
आरजेडी	तीसरे स्थान पर	मुख्य मुकाबले से बाहर

बीजेपी का किला डगमगाया, 'जन सुराज' ने दी सीधी टक्कर

पटना की बांकीपुर सीट जिसे पिछले 30 सालों से बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था, वहां इस बार जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़कर बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं।

चुनाव के दौरान के मुख्य घटनाक्रम

– रातभर थाने में हंगामा: वोटिंग से एक रात पहले जक्कनपुर थाने में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि पुलिस ने जन सुराज के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं और एजेंटों को बिना कारण हिरासत में ले लिया। सूचना मिलते ही प्रशांत किशोर देर रात थाने पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ घंटों धरने पर बैठे।

पुलिस पर गंभीर आरोप: मतदान के दिन ढङ ने कहा कि "बांकीपुर में बीजेपी नहीं, बल्कि पुलिस चुनाव लड़ रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों के टेबल हटाए जा रहे हैं और मतदाताओं को डराया जा रहा है।

ईवीएम खराबी और कम मतदान: बूथ नंबर 143 समेत कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें आईं। क्षेत्र में कुल 3.80 लाख मतदाता हैं, लेकिन वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी रही और 50% मतदान भी नहीं हो पाया।

राजनीति के जानकारों और वरिष्ठ पत्रकारों का ग्राउंड विश्लेषण: 250 से अधिक पोलिंग बूथों और 3000 से ज्यादा मतदाताओं के मूड के आधार पर तैयार आकलन में मुकाबला बेहद करीबी दिख रहा है।

5 बड़े फैक्टर:

पारंपरिक वोट बैंक में बिखराव: बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला शहरी वर्ग, लाला जी और नीतीश कुमार का पारंपरिक बेस इस बार बूथ तक उस संख्या में नहीं निकला। कम वोटिंग ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है।

स्टार प्रचारकों की फौज बेअसर: इस सीट को बचाने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह, मनोज तिवारी, सम्राट चौधरी समेत 40 से अधिक स्टार प्रचारक उतारे। इसके बावजूद शहरी वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा। पूर्व विधायक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की साख दांव पर है।

जन सुराज की सेंधमारी और साइलेंट अंडरकरंट: PK ने नालों की समस्या, सफाई और 30 साल के शासन के खिलाफ 'बदलाव' का नैरेटिव बनाया। जन सुराज के कार्यकर्ता हर बूथ पर मुस्तैद दिखे। जानकारों का मानना है कि जन सुराज के पक्ष में 'साइलेंट अंडरकरंट' है।

Gen Z और युवा वोटर्स का फैक्टर: इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू युवा वोटर्स का रुख रहा। कई परिवारों में बुजुर्ग बीजेपी के साथ दिखे, लेकिन युवा शिक्षा, रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर खुलकर बदलाव और प्रशांत किशोर के पक्ष में दिखे।

RJD रेस से बाहर: तेजस्वी यादव के रोड शो के बावजूद RJD का कैडर ढीला दिखा और वोट बैंक बिखरा। पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई है।

बीजेपी खेमे में मायूसी? : कम मतदान और कार्यकर्ताओं की बेरुखी के कारण बीजेपी खेमे में धड़कनें बढ़ी हुई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर बांकीपुर जैसी सुरक्षित सीट पर हार होती है तो यह बीजेपी और ठऊ्ञ के लिए 2025–2029 से पहले बड़ा झटका होगा।

दतिया उपचुनाव – नरोत्तम का टिकट कटा, साख की लड़ाई

मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बीजेपी में बगावत के सुर उठे थे, जिसे शांत करने के लिए उट मोहन यादव को खुद मोर्चा संभालना पड़ा।

मुख्य समीकरण

बीजेपी प्रत्याशी: आशुतोष तिवारी – संगठन के नेता, जिन्हें उट मोहन यादव का समर्थन प्राप्त है।

कांग्रेस प्रत्याशी: घनश्याम सिंह – राजपरिवार से ताल्लुक, 2 बार के पूर्व विधायक।

अंदरूनी कलह: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद समर्थकों ने पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर विरोध जताया था।

नरोत्तम का बयान: उन्होंने कहा कि "जनता विकास और बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी।"

यहां हार–जीत का असर सीधे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और उट मोहन यादव vs नरोत्तम मिश्रा के समीकरण पर पड़ेगा। दोनों उपचुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। बांकीपुर में जनता 'बदलाव' चाहती है या 'स्टेटस को' बरकरार रखेगी, और दतिया में बीजेपी अपने बागी तेवर संभाल पाती है या नहीं, यह 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही साफ होगा।

शुक्रवार सुबह 2 जगह बुजुर्ग महिलाओं से चेन स्नेचिंग

प्रियदर्शनी परिसर और सेक्टर–1 में एक्टिवा–मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई में शुक्रवार सुबह–सुबह भट्टी और सुपेला थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की दो अलग–अलग घटनाएं सामने आई। दोनों ही घटनाओं का शिकार बुजुर्ग महिलाएं हुईं। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

पहली घटना : प्रियदर्शनी परिसर में एक्टिवा सवारों ने तोड़ी चेन

सुपेला थाना क्षेत्र के प्रियदर्शनी परिसर स्थित भाजपा कार्यालय के पास सुबह करीब 6 बजे घर के सामने टहल रही एक बुजुर्ग महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक्टिवा वाहन पर सवार दो युवक आए। वाहन चालक ने हेलमेट पहना था जबकि पीछे बैठे व्यक्ति ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। उन्होंने महिला के गले से करीब 3 तोले की सोने की चेन खींची और फरार हो गए। भागते समय चेन टूटकर घटनास्थल पर ही गिर गई, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

दूसरी घटना : सेक्टर–1 में मिर्ची पाउडर फेंककर खींची चेन

दूसरी वारदात भट्टी थाना क्षेत्र के सेक्टर–1, सड़क–2 के पास सुबह 6:11 बजे हुई। यहां फूल तोड़ रही एक बुजुर्ग महिला को पहले चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका गया। इसके बाद 45–50 वर्षीय साड़ी पहनी महिला ने महिला के गले से चेन खींची और पास खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठे पुरुष के साथ भाग निकली।

पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी खंगाले जा रहे

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विजय अग्रवाल, भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी, सुपेला थाना प्रभारी निरीक्षक शिवनारायण सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों महिलाओं से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है।

पुलिस का कहना है कि दोनों घटनाओं में शामिल आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र की महिलाओं में दहशत का माहौल है।

राजनांदगांव में अलर्ट : मोंगरा बांध सहित कई गेट खुले

शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा, SP अंकिता शर्मा का निर्देश- नदी किनारे सतर्कता बरतें, निचले इलाकों में रह रहे लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते मोंगरा बांध सहित अन्य कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। इससे जिले की शिवनाथ नदी और अन्य नदियों का जलस्तर सामान्य से अधिक बढ़ने की संभावना है।

पुलिस ने शुरू की निगरानी और जागरूकता अभियान: स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को तत्काल निर्देश जारी किए हैं।

नदी और बांधों के आसपास बसे गांवों में मुनादी और माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नदी किनारों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं और पुलिस टीमों को गश्त पर तैनात किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदी, नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाएं और बच्चों को भी दूर रखें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

क्या है प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जलस्तर की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाना/चौकी से संपर्क करने को कहा गया है।

एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन, राजस्व और SDRF की टीमें भी अलर्ट पर हैं। स्थिति सामान्य होने तक नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है।

छत्तीसगढ़ में नकली 'एनालॉग पनीर' बनाने–बेचने पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्री जसवाल का बड़ा फैसला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में नकली 'एनालॉग पनीर' के निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जसवाल ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है। **स्वास्थ्य के लिए था हानिकारक :** जानकारी के अनुसार प्रदेश में मिल्क पाउडर से बनाए जा रहे एनालॉग पनीर की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी। इस नकली पनीर के सेवन से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने की शिकायतें मिल रही थीं। एनालॉग पनीर में दूध की जगह अन्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के लिए हानिकारक साबित हो रहा था। **बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई :** स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेशभर में एनालॉग पनीर की जांच की जाए और इसे बनाने व बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने कहा कि आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

साई नगर उरलावासियों ने अधूरी नाली निर्माण को पूरा कराने कलेक्टर को दिया आवेदन

महिला स्व-सहायता समूह ने मछली पालन के लिए डबरी लीज पर देने की मांग की, वर्षों से स्थापित मोबाइल टॉवर एवं अन्य उपकरणों को अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं हटाए जाने की शिकायत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर सोनल डेविड भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 98 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 58 साईं नगर उरला वासियों ने अधूरे नाली को पूरा कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व गली में सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन नाली निर्माण कार्य आधा ही किया गया, जिससे पानी निकासी की समस्या बनी हुई है। खाली जगहों में पानी जमा होने से मच्छर, कीड़े-मकोड़ों का खतरा बना रहता है। लगभग 200 मीटर शेष नाली निर्माण के लिए नगर निगम में आवेदन किया गया है। स्थानीय निवासियों ने दोनों ओर शेष नाली निर्माण

कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

बनियापारा दुर्ग निवासी ने सुभाष नगर कन्हैयापुरी कसारीडीह में पिछले करीब 18 वर्षों से स्थापित मोबाइल टॉवर एवं अन्य उपकरणों को अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद भी नहीं हटाए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि टॉवर का अनुबंध वर्ष 2023 में समाप्त हो गया था। कंपनी के अनुरोध पर टॉवर हटाने के आश्वासन के साथ अवधि बढ़ाई गई, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी टॉवर नहीं हटाया गया। कई बार संपर्क करने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लंबे समय से टावर लगे होने के कारण मकान की छत क्षतिग्रस्त हो रही है। इस पर कलेक्टर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम पंचायत माटरा की महिला शक्ति संगठन स्व-सहायता समूह ने गजानंद डबरी को मछली पालन के लिए लीज पर देने की मांग की है। समूह की 11 सक्रिय महिला सदस्य डबरी में मछली पालन कर स्वरोजगार से जुड़ना चाहती हैं। महिला समूह ने बताया कि इस संबंध में पिछले वर्ष भी ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कर आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। महिला सदस्यों ने स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने उप संचालक मत्स्योद्योग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

खास खबर

तकनीकी समस्या के कारण किसी शिक्षक का वेतन नहीं कटेगा : मंत्री गजेंद्र यादव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

85 प्रतिशत शिक्षक रोज लगाते है ऑनलाइन अटेंडेंस

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों द्वारा श्रङ ऐप में आ रही तकनीकी त्रुटियों एवं एरर संबंधी शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रङ ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री यादव ने बताया कि संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को श्रङ ऐप में आ रही सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 अगस्त तक ऐप में आ रही तकनीकी खामियों का समाधान कर इसे पूरी तरह सुचारु बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिल सके। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से लगभग डेढ़ लाख शिक्षक लगभग 85 प्रतिशत शिक्षक प्रतिदिन VSK ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक केवल शिक्षण कार्य ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार उनके इस सहयोग, अनुशासन और समर्पण का सम्मान करती है। शिक्षकों के सुझावों और अनुभवों के आधार पर श्रङ ऐप को और अधिक सरल, उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जाएगा। गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुविधा और हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी शिक्षक को तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई आती है, तो उसके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। किसी भी शिक्षक को तकनीकी खामी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा।

उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे पूर्व की भांति श्रङ ऐप का उपयोग करते रहें तथा यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या सुझाव हो तो उसे संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुँचाएँ। सरकार प्रत्येक सुझाव का सकारात्मक परीक्षण कर आवश्यक सुधार करेगी, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं तकनीक-सक्षम बन सके।

ओबीसी महासभा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी गणना और 27% आरक्षण की मांग

दुर्ग। ओबीसी महासभा, प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आव्हान पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव के नेतृत्व में ओबीसी महासभा दुर्ग के पदाधिकारियों ने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के नाम प्रेषित किया गया।

तीन प्रमुख मांगे : ज्ञापन में ओबीसी समाज के हित में तीन प्रमुख मांगें रखी गईं जिसमें राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी गणना की जाए। वन नेशन-वन रिजर्वेशन के तहत ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए और ओबीसी कृषि भूमि संरक्षण अधिनियम बनाया जाए।

जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि ओबीसी समाज की वास्तविक संख्या और स्थिति का पता लगाने के लिए जनगणना में गणना जरूरी है। साथ ही देशभर में आरक्षण में एकरूपता लाने और कृषि भूमि के संरक्षण के लिए कानून बनाना समय की मांग है। ज्ञापन सौंपते समय जिला अध्यक्ष भानु प्रताप यादव के साथ यशवंत साहू, प्रशांत सोनी, धांसू देशमुख, संजय साहू, बसंत साहू सहित ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल और समस्याओं को लेकर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन

प्रभावित उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (शहर) की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक जिला अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में राजीव भवन, दुर्ग में संपन्न हुई। बैठक में स्मार्ट मीटर, बढ़े हुए बिजली बिल, जनसमस्याओं तथा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी चरणबद्ध जनआंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि स्मार्ट मीटर एवं बढ़े हुए बिजली बिलों से प्रभावित उपभोक्ताओं के घर-घर जाकर उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे, ताकि आम जनता की शिकायतों का व्यवस्थित संकलन कर शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखा जा सके। इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक समान आवेदन प्रारूप तैयार कर सभी वार्डों एवं बूथों तक उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कहा कि आज प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल आम नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। आम उपभोक्ता बिना कारण बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान है और सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय केवल वसूली पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में भी स्मार्ट मीटर एवं बिजली बिल के मुद्दे पर व्यापक जनआंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। उसी के अनुरूप दुर्ग शहर में भी चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।

धीरज बाकलीवाल ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों एवं वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया कि 31 जुलाई तक प्रत्येक वार्ड, मंडल एवं बूथ स्तर पर बैठकें आयोजित कर संगठन को और अधिक सक्रिय बनाया जाए। प्रत्येक बूथ तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करते हुए घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा तथा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें एकत्रित कर संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनहित की लड़ाई भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि आम जनता को राहत दिलाना है। यदि सरकार ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कांग्रेस पूरे जिले में व्यापक जनआंदोलन छेड़ेगी।

बैठक में संगठन विस्तार पर भी विशेष चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाया जाएगा, ताकि जनहित के प्रत्येक मुद्दे पर कांग्रेस प्रभावी ढंग से जनता के बीच कार्य कर सके। बैठक का संचालन जिला संगठन महामंत्री रायसिंह दिकोला ने किया तथा अंत में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशील भारद्वाज ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल, आर.एन. वर्मा, रायसिंह दिकोला, अल्ताफ अहमद, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, आनंद देव ताम्रकार, देवश्री साहू, मनीष बघेल, अब्दुल गनी, शिव वैष्णव, सुभाष पाल, सुशील भारद्वाज, विकास सापेकर, संजय बत्रा, मीना पॉल, एन. जेम्स, नंदा राउत, सुनीत घोष, राजा विक्रम बघेल, भूपेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा, जमुना साहू, राकेश ठाकुर, चंद्रमोहन गभाने, दीपक जैन, अभिनव बघेल, विमल यादव, त्रिशरण डोंगरे, रवि कोरिया, अनूप पाटिल, खुर्शीद अहमद, जगमोहन ढीमर, वेंकट साई शास्त्री, ज्ञानू बांगड़े, भूपेंद्र सेन, फिरोज खान, गौरव उमरे, अली असगर, ललित उइके, चिराग शर्मा, संजय धनकर नंदकिशोर शर्मा, बृजमोहन तिवारी, अशोक मेहरा, मोहित वाल्दे, शाहिद खान, राजू भाटिया, विनोद सेन ,दुष्यंत देवांगन, देवसेना, संजू धनकर ,मनीष सोनवाने ,शिशिरकांत कसार ,राजा विक्रम बघेल ,अशोक मेहरा ,विकाश सापेकर, बृजमोहन ढीमर, अनीश रजा , राकेश साहू राकेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जिला, ब्लॉक एवं मंडल स्तर के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इंजीनियरिंग व विज्ञान के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार और पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने की आवश्यकता : प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इंजीनियरिंग और विज्ञान शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों तथा पर्यावरण अध्ययन को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी भविष्य की सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत सरकार के विशेष मॉनिटर प्रो. कन्हैया त्रिपाठी ने कही।

प्रो. त्रिपाठी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई के अपने प्रवास के दौरान संस्थान के नेतृत्व, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिवनाथ हॉस्टल का दौरा कर नवागंतुक विद्यार्थियों से भी मुलाकात की। भावी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को समाज की व्यापक समझ से लैस करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रो. त्रिपाठी ने समकालीन सामाजिक चुनौतियों, लैंगिक समानता, मानवाधिकारों और विद्यार्थियों के समग्र कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण एक प्रगतिशील तथा समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देगा और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा।

आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश एवं संस्थान के डीन मंडली ने प्रो. त्रिपाठी का स्वागत किया तथा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न पहलों की जानकारी दी। जनजातीय विकास और छात्र कल्याण के क्षेत्र में आईआईटी भिलाई के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रो. त्रिपाठी ने संस्थान को लैंगिक समानता और मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को दस्तावेज के रूप में सहेजने के लिए प्रोत्साहित किया।

बातचीत के दौरान प्रो. त्रिपाठी ने आईआईटी भिलाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों के माध्यम से संस्थागत संबंधों को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मानवाधिकारों और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान के हैप्पीनेस क्लब का नाम बदलकर ह्यूमन राइट्स एंड हैप्पीनेस क्लब करने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा, उन्होंने छत्तीसगढ़ में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लिकेशन विकसित करने तथा विभिन्न आईआईटी एवं एनआईटी के विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय इनोवेशन फेयर आयोजित करने का प्रस्ताव दिया।

3500 रूपए प्रति क्विंटल के भाव धान खरीदे सरकार - छग प्रगतिशील किसान संगठन की मांग

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी को ज्ञापन दिया। संगठन के ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 3 साल से सरकार 3100 रूपए प्रति क्विंटल के स्थिर भाव से किसानों का धान खरीद रही है इस प्रकार पिछले 3 साल से राज्य के किसानों की आय भी स्थिर है जबकि पिछले 3 सालों में उत्पादन लागत और बाजार की मंहगाई में 50% की वृद्धि हुई है इस आधार पर किसानों की आय कम हो गई है। खाद और डीजल संकट के कारण इस खरीफ सीजन में प्रति एकड़ उत्पादन लागत 5-6 हजार बढ़ गई है किसानों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है इसी आधार पर किसानों ने इस खरीफ सीजन का धान 3500 रूपए प्रति क्विंटल के भाव से करने और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अगले सालों में धान 8% अधिक भाव में खरीदने की मांग भी उठाई है।

अन्य उपज लेने वाले किसानों को भी उन्नत करे सरकार

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में किसान संगठन ने कहा है कि एच एम टी, श्रीं राम, बासमती, दुबराज, जंवाफूल जैसे पतले और सुगंधित धान का उत्पादन करने वाले हजारों किसानों को कृषक उन्नति योजना में शामिल नहीं किया गया है इसी प्रकार उद्यानिकी, वानिकी, औषधीय, फल, फूल, पशु चारा आदि की उपज लेने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के लाभ से वंचित रखा गया है जबकि राज्य में लाखों किसान लगभग 8-10 लाख हेक्टेयर में इनकी उपज लेते हैं किसान संगठन ने कहा है कि अन्य उपज लेने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जाए।

अमेरिका के ट्रेडडील खेती किसानी और किसान हो जाएगा तबाह

मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को प्रेषित ज्ञापन में किसान संगठन ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि अमेरिका से कृषि उपज और डेयरी उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात से मक्का, दलहन, तिलहन, कपास आदि की खेती किसानी और किसान तबाह हो जायेंगे मूल्य के प्रतिस्पर्धा में हमारे यहां के किसान टिक नहीं पायेंगे अतः किसानों के हित में अमेरिका के साथ ट्रेडडील न किया जाए।

स्व. प्यारेलाल बेलचंदन की जयंती पर किसानों, शिक्षा और ग्राम विकास में योगदान को किया नमन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शिक्षा, समाज सेवा एवं ग्राम विकास के अग्रदूत स्व. दाऊ कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन की 99वीं जयंती बुधवार को सेजेस दाऊ कुर्मी स्व. प्यारे लाल बेलचंदन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधी ग्राम तिरगा में श्रद्धा, गरिमा और उत्साह के साथ मनाई गई। गुरु पूणिर्मा के पावन अवसर पर आयोजित इस समारोह में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, समाजसेवियों, पालकों, विद्यार्थियों एवं आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ स्व. दाऊ कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात गुरु पूणिर्मा के अवसर पर विद्यालय परिसर में अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधों की देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत सदस्य दामिनी मुकेश साहू ने की। विशिष्ट अतिथियों में सेवा दल के जीवित सदस्य गुहाराम देशमुख, स्व. दाऊ कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन के सुपुत्र एवं किसान संगठन के पूर्व अध्यक्ष गोपेन्द्र किशोर बेलचंदन, मोहनलाल हरमुख पूर्व अध्यक्ष जनपद दुर्ग) ग्राम पंचायत तिरगा के सरपंच

घसियाराम देशमुख, ग्राम पंचायत झोला की सरपंच बसंती निषाद तथा ग्राम पंचायत भोथली की सरपंच नेमीन खुटेल उपस्थित रहीं।

मुख्य अतिथि प्रीतपाल बेलचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्व. दाऊ कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन का जीवन त्याग, सेवा, शिक्षा और जनकल्याण का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दाऊजी ने ग्रामीण विकास, शिक्षा विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए जो कार्य किए, वे आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से उनके आर्दशों को आत्मसात कर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया तथा विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित इस गरिमामय आयोजन की सराहना की।

गुरु पूणिर्मा के अवसर पर सेजेस दाऊ कुर्मी स्व. प्यारे लाल बेलचंदन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधी ग्राम तिरगा परिवार द्वारा शिक्षा जगत में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भूतपूर्व शिक्षकों हीरालाल दिल्लीवार, अभयराम बेलचंदन, सुरेश ऋषि एवं साहित्यकार विजय दिल्लीवार का श्रीफल एवं सम्मान सामग्री भेंटकर सम्मान किया गया। साथ ही विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यालय स्टाफ का भी सम्मान किया गया।

समारोह के दौरान वक्ताओं ने ग्राम तिरगा के गौरवशाली इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले खरखरा नदी की बाढ़ से गांव का अस्तित्व संकट में था। उस समय स्व. प्यारेलाल बेलचंदन के पिता एवं तत्कालीन मालगुजार दाऊ भंगीराम बेलचंदन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने श्रमदान कर खरखरा नदी की धारा मोड़कर गांव को विनाश से बचाया। लगभग साढ़े चार माह तक ग्रामीणों ने कुदाली, गैंती, बेलचा और बैलगाड़ियों की सहायता से अथक परिश्रम किया तथा दाऊ भंगीराम बेलचंदन ने इस कार्य के लिए अपनी निजी भूमि भी उपलब्ध कराई। इसे देश की पहली ऐसी घटना माना जाता है, जब किसी गांव को बचाने के लिए सामूहिक श्रमदान से नदी की धारा बदली गई। इस ऐतिहासिक कार्य को देखने तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू तथा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्लूजी राजू सहित अनेक वरिष्ठ नेता तिरगा पहुंचे थे। वक्ताओं ने कहा कि स्व. दाऊ कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन ने अपने पिता की सेवा,

श्रमदान और जनकल्याण की इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, समाज सेवा और ग्राम विकास के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया।

वक्ताओं ने स्व. दाऊ कुर्मी प्यारेलाल बेलचंदन के कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में दिए गए योगदान को भी विशेष रूप से याद किया। उन्होंने कहा कि भरदा कलाझमोहदी पाट क्षेत्र के किसानों के लिए स्व. दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन किसी भगवान से कम नहीं हैं। उनकी दूरदर्शी सोच से साकार हुई सिंचाई परियोजना ने क्षेत्र की धरती की प्यास बुझाई और हजारों किसानों को स्थायी सिंचाई का सहारा दिया। आज भी खरीफ सीजन में पानी की कमी होने पर किसान इस परियोजना और बेलचंदन जी को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। गर्मी के दिनों में भी निस्तारी जल की उपलब्धता बनी रहती है, जो उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है।

वक्ताओं ने बताया कि इस परियोजना को स्वीकृति दिलाने के लिए स्व. दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन ने अनेक बार भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों से मुलाकात कर अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने की सहमति प्राप्त की और परियोजना को मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनहित को सवीपरि रखते हुए अपने राजनीतिक हितों की भी परवाह नहीं की। किसानों के हित में किया गया उनका यह योगदान आज भी पूरे क्षेत्र में सम्मान और कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है।

कार्यक्रम में पालक समिति के अध्यक्ष युवराज देशमुख, संकुल प्रभारी रघुनाथ देशमुख, पूर्व जनपद सदस्य मोहनलाल हरमुख, टीकू दिल्लीवार, ऐमन देशमुख, (भूपेंद्र बेलचंदन सांसद प्रतिनिधि), परसराम देशमुख, गैंदालाल देशमुख, बिसौव देशमुख, नंद कुमार देशमुख, विनय ठाकुर, सूरज देशमुख, वीरेंद्र निषाद, नंदलाल देशमुख, पूर्व सरपंच नंद कुमार देशमुख, देवीसिंग ठाकुर फिरोज बेलचंदन, दयाराम दिल्लीवार, महेश कुमार बेलचंदन, श्यामू देशमुख, मोहन देशमुख सहित सेजेस दाऊ कुर्मी स्व. प्यारे लाल बेलचंदन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधी ग्राम तिरगा के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यालय स्टाफ, पालकगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों एवं उपस्थितजनों का आभार व्यक्त किया।

रेल नेटवर्क का विस्तार छग के संतुलित व समावेशी विकास का मजबूत आधार बनेगा : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में प्रमुख रेल परियोजनाओं को गति देने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की विस्तृत चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना के विस्तार, नई रेल परियोजनाओं तथा लंबित रेल लाइनों की प्रगति के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे उपस्थित थे।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक, खनिज एवं कृषि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार केवल यातायात सुविधा का विषय नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन, कृषि विपणन, जनजातीय अंचलों के विकास तथा क्षेत्रीय संतुलित प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में रेल अधोसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है और राज्य सरकार इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य कर रही है।

बैठक में कटघोरा–डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन परियोजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि लगभग 295 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का विकास रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए दोनों संस्थाओं की साझेदारी में एक स्पेशल परपज व्हीकल का गठन किया जाएगा। यह रेल लाइन कटघोरा से करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी तथा ऐसे अनेक क्षेत्रों को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जहां अब तक रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा लाखों नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

बैठक में रावघाट–जगदलपुर रेलवे लाइन परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 140 किलोमीटर लंबी इस महत्वपूर्ण रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा चुकी है तथा रेलवे द्वारा निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने से बस्तर अंचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तीन अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं – सरडेगा–पत्थलगांव–अंबिकापुर (244 किलोमीटर), धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा (301 किलोमीटर) तथा अंबिकापुर–बरवाडीह (200 किलोमीटर) – को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल संपर्क व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा व्यापार, पर्यटन, खनिज परिवहन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान किरंदुल–कोत्तागुडेम (180 किलोमीटर) तथा गढ़चिरौली–बीजापुर–किरंदुल (बचेली) (490 किलोमीटर) नई रेल लाइन परियोजनाओं के सर्वे कार्य की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर आगामी कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया, जिससे बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो सके तथा विकास एवं सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को गति मिले।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई रेल परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि उत्पादों की सुगम आवाजाही, पर्यटन संवर्धन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ का रेल नेटवर्क आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगा तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति मिलेगी।

खास खबर

मलेरिया पर निर्णायक प्रहार जारी, एक भी मृत्यु न हो यही हमारा लक्ष्य : स्वास्थ्य मंत्री

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बस्तर अंचल में संचालित मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसके माध्यम से लाखों लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं तथा गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार संभव हुआ है। रायपुर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34.29 लाख से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो लक्षित आबादी का लगभग 99 प्रतिशत है। अभियान के दौरान मलेरिया, टीबी, सिकल सेल, कुष्ठ रोग, मुख कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की पहचान कर समय पर उपचार प्रारंभ किया गया। वहीं 60 हजार से अधिक गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया गया तथा 10,938 उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी और उपचार सुनिश्चित किया गया।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में मलेरिया के कुछ मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी सतकर्ता के साथ कार्य कर रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम और मैदानी अमला गांव–गांव पहुंचकर जांच, उपचार, सर्वेक्षण और जनजागरूकता गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया से एक भी मृत्यु न हो, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए समय पर जांच, त्वरित उपचार, सतत निगरानी और सामुदायिक जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि रणनीतिक काययीजना, सतत निगरानी और जनसहभागिता के परिणामस्वरूप बस्तर संभाग की मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.60 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत रह गई है। वहीं राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई) 5.21 से घटकर 0.90 तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि मलेरिया नियंत्रण की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों को दर्शाती है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विगत ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.89 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव सम्पन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित विशेषज्ञ जांच, उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की पहचान तथा आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है।

आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में 375 नई 108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित की गई हैं। जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच 6.50 लाख से अधिक नागरिकों को समयबद्ध आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे दुर्घटना, प्रसूति एवं अन्य आपात परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो सकी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए भ्स्स् स्पमिबंतम स्पउपजमक के सहयोग से राज्य के 1,051 स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक पैथोलॉजी जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हब एंड स्पोक मॉडल, आईटी आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली एवं गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को भी विश्वसनीय और समयबद्ध जांच सुविधियां उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ–साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक तकनीकी एवं पैरामेडिकल मानव संसाधन उपलब्ध होंगे तथा प्रदेश के युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नए अवसर प्राप्त होंगे।

महानदी विवाद नहीं, छत्तीसगढ़–ओडिशा की साझा समृद्धि का आधार बने : मुख्यमंत्री साय

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल की पहल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के सौहादर्पूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक–दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा तथा उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख एवं व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय–समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे।

मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर अधिकतम विषयों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए तथा केवल नीतिगत महत्व के विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर विचार के लिए लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने, समयबद्ध काययीजना तैयार करने तथा दोनों राज्यों के बीच दीघर्कालिक सहमति आधारित समझौते का प्रारूप तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल दोनों राज्यों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी तथा समाधान की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच समन्वय की भावना ने वर्षों से लंबित जटिल विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में दोनों राज्य मिलकर ऐसा समाधान विकसित करेंगे, जिससे किसानों, नागरिकों, उद्योगों, पर्यावरण तथा भावी पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बने। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिक्षा से ही होता है सशक्त राष्ट्र का निर्माण, बड़े लक्ष्य तय कर पूरी निष्ठा से करें पढ़ाई : मंत्री टंक राम वर्मा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर धमतरी स्थित मराठा मंगल भवन में जिला स्तरीय 'शाला प्रवेशोत्सव' का आयोजन किया गया। समारोह में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा के साथ भावुक व आत्मीय स्वागत किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री श्री वर्मा ने छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं शाला गणवेश प्रदान किए। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया। दिव्यांग विद्यार्थियों को आवश्यक सहायक किट वितरित कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसी तरह शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक व सह–शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

जिले के प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, शिक्षक, चिकित्सक और राष्ट्र निर्माता बनेगा। विद्यार्थियों में उत्साह भरने के लिए उन्होंने संत और तीन मजदूरों की एक प्रेरक कथा साझा की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक मजदूर की सकारात्मक सोच और स्पष्ट लक्ष्य ने साधारण से पत्थर तोड़ने के काम को 'बांध निर्माण' जैसे महान राष्ट्रसेवा के कार्य में बदल दिया। उन्होंने कहा कि काम केवल हाथों से नहीं, बल्कि उद्देश्य और सोच से बड़ा बनता है। मंत्री श्री वर्मा ने विद्यार्थियों से केवल अंक लाने तक सीमित न रहकर ज्ञान और संस्कारों के माध्यम से समाज सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया।

मंत्री श्री वर्मा ने नूतन विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर 'न्योता भोजन' किया, जिससे विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति अपनापन और उत्साह का संचार हुआ।

जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालीन सुचारू संचालन के लिए जल संचय और जल संरक्षण जरूरी–अरुण साव

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों के लिए ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर राज्य स्तरीय कायर्शाला में शामिल हुए। उन्होंने नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यशाला में महिला सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि जल आपूर्ति की योजनाओं के लंबे समय तक सुचारू संचालन के लिए बारिश के पानी का संचय और जल संरक्षण आवश्यक है। यह भूजल को रिचार्ज करने के साथ ही दीर्घ काल तक जल स्रोतों में जल की उपलब्धता बनाए रखेगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यशाला में सरपंचों से गांवों में हर घर नल से जल पहुंचने के बाद ग्रामीणों, खासकर महिलाओं के जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने नल जल योजनाओं के संचालन–संधारण के लिए पंचायतों द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने गांवों में जलस्रोतों, जल की गुणवत्ता के नियमित परीक्षण तथा रखरखाव शुल्क की भी जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा यूनिसेफ और एसीई संस्था के सहयोग से इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 100 महिला सरपंच शामिल हुईं।

कार्यशाला में हर घर जल प्रमाणित गांवों में नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और मरम्मत पर व्यापक विचार–विमर्श और बेस्ट प्रेक्टिसेस पर गहन चर्चा की गई। महिला सरपंचों ने इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत अपनी–अपनी पंचायतों में जल आपूर्ति की व्यवस्था तथा नल जल योजना के संचालन–संधारण के अनुभव साझा किए। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महिला सरपंचों को नल जल योजनाओं के सफल, निर्बाध और दीर्घकालीन संचालन के गुर बताए।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यशाला में कहा कि जल आपूर्ति के लिए उपयोग हो रहे जल स्रोतों की देखभाल और सावधानीपूर्वक उपयोग जरूरी है। इसके टिकाऊपन पर ही योजना की दीर्घकालीन सफलता निर्भर है। उन्होंने कहा कि नल जल योजनाओं के काम पूर्ण होने तथा पंचायतों को इसके हस्तांतरण के बाद इसका संचालन व संधारण ग्राम पंचायतों को करना है। जल जीवन मिशन हमारे घर और हमारे गांव के लिए योजना है। ग्राम पंचायतों को गांववालों के साथ मिलकर जल आपूर्ति की व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है।

बस्तर आज शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति भवन के विशेष अतिथि बने बस्तर के मांझी–चालकी : बस्तर पंडुम–2026 के विजेताओं और जनजातीय प्रतिनिधियों का हुआ विशेष सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

बस्तर की लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व की गौरवशाली विरासत ने आज राष्ट्रपति भवन में इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडुम–2026 के विजेता प्रतिभागियों, परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में आत्मीय स्वागत किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर पंडुम–2026 के विजेताओं, परगना मांझी, मांझी, चालकी तथा पद्मश्री सम्मानित विभूतियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में अत्यंत दुर्लभ और आत्मीय दृश्य तब देखने को मिला, जब राष्ट्रपति ने स्वयं सभी अतिथियों को भोजन परोसकर उनका सम्मान किया। राष्ट्रपति की इस सहज आत्मीयता ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया। प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, बस्तर के पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व के प्रतिनिधि, बस्तर पंडुम–2026 के विजेता कलाकार, पद्मश्री सम्मानित विभूतियाँ, जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से आत्मीय संवाद करते हुए बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोककला, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, मांझी–चालकी प्रणाली तथा बस्तर पंडुम के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कलाकारों और जनजातीय प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत भारत की अमूल्य धरोहर है और उसका संरक्षण पूरे देश का दायित्व है।

राष्ट्रपति ने जताई बस्तर आने की इच्छा : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आग्रह पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भविष्य में बस्तर दशहरा एवं बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा उनके हृदय को विशेष रूप से स्पर्श करता है। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ की काष्ठ निर्मित प्रतिमा तथा बस्तर दशहरा की अद्वितीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बस्तर दशहरा से विशेष आत्मीय संबंध रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मांझी उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनके पिता भी मांझी थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की परंपरागत नेतृत्व व्यवस्था सामाजिक एकता, सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक संरक्षण की सशक्त आधारशिला है।

बस्तर पंडुम ने संस्कृति को दिलाई नई पहचान : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि बस्तर पंडुम छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने बस्तर की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ–साथ पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर के कलाकार, शिल्पकार और युवा अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

बस्तर विकास और शांति की नई पहचान बन रहा है : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों और स्थानीय जनभागीदारी के परिणामस्वरूप बस्तर आज शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर में आया यह सकारात्मक परिवर्तन पूरे देश के लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है। उन्होंने मांझी एवं चालकी की भूमिका की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि वे समाज और प्रशासन के बीच प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

पहली बार राष्ट्रपति भवन में दिखा बस्तर का ऐसा वैभव – अमित शाह

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति भवन आए हैं, किंतु पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बस्तर की पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल को एक साथ देखा है। उन्होंने कहा कि यह दृश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय गौरव का अद्भुत प्रतीक है।

मुख्यमंत्री बोले झ यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से बस्तर के प्रतिनिधिमंडल की यह आत्मीय भेंट पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर अंचल के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएँ और सांस्कृतिक विरासत देश के सर्वोच्च संवैधानिक मंच पर सम्मानित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर आज शांति, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा दिलाई है तथा स्थानीय कलाकारों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को नया मंच प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति से गहरा आत्मीय जुड़ाव है। उनके अनुभव, स्नेह और मार्गदर्शन से बस्तर की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि उनके आगमन से बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक पहचान मिलेगी तथा जनजातीय समाज का उत्साह और बढ़ेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन का भ्रमण भी किया तथा भारत की लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक विरासत से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों और महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत हुआ। राष्ट्रपति को भेंट की गई बस्तर की 300 वर्ष पुरानी 'झिटकू–मिटकी' की अनुपम कलाकृति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को बस्तर की लगभग 300 वर्ष पुरानी लोकगाथा 'झिटकू–मिटकी' पर आधारित विशेष कलाकृति स्मृति–चिह्न स्वरूप भेंट की। यह कलाकृति बस्तर की जनजातीय संस्कृति, प्रेम, समर्पण, लोकआस्था और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है।

लोकमान्यता के अनुसार कठिन अकाल के समय झिटकू और मिटकी ने अपने प्रेम, त्याग और समर्पण की ऐसी अमिट मिसाल प्रस्तुत की कि उन्हें देवतुल्य सम्मान प्राप्त हुआ। आज भी बस्तर अंचल में झिटकू को 'खोड़िया राजा' तथा मिटकी को 'गप्पा देई' के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, विशेष सचिव रजत बंसल, संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह, संस्कृति एवं राजभाषा विभाग के संचालक संजय कन्नौजे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संपादकीय

जहां भाषा खत्म हो जाती है,वहां से गाली शुरू होती है

सभ्य समाज,सभ्य लोगों की अपनी एक भाषा होती है जिसमें वह अपने विचार व भाव को प्रकट करता है।अपने दुख,सुख,संवेदना को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को आपस जोड़ते हैं।इस हिसाब से देखा जाए तो भाषा सकारात्मक होती है।हमारी भाषा से लोगों को पता चलता है कि हम क्या है, कैसे है,सभ्य हैं, शालीन हैं।एक तरह से हमारी भाषा हमारे बारे में दूसरों को बताती है,दूसरे हमको हमारी भाषा के जरिए भी जानते हैं कि हम कितने सभ्य है, हम कितने शालीन हैं।हम एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं,एक दूसरे का कितना आदर करते हैं।हमारी भाषा से हमारी स्थिति का भी पता चलता है,हम दुख में होते हैं तो हमारी भाषा अलग होती है, हम सुख में होते हैं तो हमारी भाषा अलग होती है।लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी भाषा में गालियां होती है और जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी भाषा खो जाती है,हमारी भाषा खत्म हो जाती है, हम बहुत सारी गालियां देते हैं।इसलिए कहा जाता है कि जहां हमारी भाषा खत्म हो जाती है,वहां से गाली शुरू होती है।जब गाली खत्म हो जाती है तो आपस में मारपीट शुरू हो जाती है।हमारे देश में आजादी के बाद से आंदोलन होते रहे हैं, नारेबाजी होती रही है,आंदोलन में गाली कभी नही दी गई।आंदोलन में गाली का उपयोग कभी नहीं किया गया इसीलिए जब सीजेपी के आंदोलन में गालियों वाले भद्दे पोस्टर,युवाओं ने भद्दी गाली दी,खूब हिंसा हुई,तोड़फोड़ हुई तो लोगों को बुरा लगा है,लोगों ने कहा है यह कैसा आंदोलन है।

हम लोगों ने पढ़ा है कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन देश की आजादी के लिए किया गया आंदोलन था। तब देश की आजादी के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले नारे लगाए जाते थे। तुम मुझे खून दो,मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिध्द अधिकार है। आजादी के बाद होने वाले आंदोलनों में भी खूब नारे लगते रहे हैं।इंकलाब जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी,अपना हक हम लेकर रहेंगे, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आंदोलन चाहे किसी संस्था के खिलाफ है,किसी राज्य सरकार के खिलाफ है या केंद्र सरकार के खिलाफ है, आंदोलन में किसी को गाली नहीं दी जाती थी। पिछले एक दशक में हुए आंदोलन में किसी नेता का बुरा जरूर चाहा गया है, कहा गया मर जा मोदी, कहा गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मौत का सौदागर,दस सिर वाला रावण आदि कहा गया। बिहार चुनाव के समय तो पीएम मोदी को मां की गाली दी गई। इससे राजनीति में भाषा का स्तर गिरा और गिरता चला गया है।सीजेपी के आंदोलन से तो साफ हो गया है कि आने वाली पीढ़ी की भाषा कितनी खराब हो गई है।उसके पास अपने गुस्से को प्रकट के लिए अच्छे शब्द नही है, उसके पास गुस्से का प्रकट करने के लिए गंदी भाषा, गंदे मीम हैं, गंदे पोस्टर हैं।वह पुरानी पीढ़ी को निश्चित तौर पर बुरे लगेंगे कि क्योंकि पुरानी पीढ़ी की भाषा में मर्यादा का ख्याल रखा जाता था, अपने विचार व गुस्से को अच्छे शब्दों में प्रकट करने की काबिलियत थी।

यही वजह है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल होने वाले जेन जी की भाषा को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो कई लोग उनका पक्ष ले रहे हैं।कंगना रनौत का तो कहना है कि जंतर–मंतर में हुए विरोध प्रदर्शन से जुडे.सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को गंदगी,कचरे और भद्देपन का प्रदर्शन है। उनका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी एक जगह इतना भद्दापन नहीं देखा।कुछ लोग कहते हैं कि जेनजी की भाषा शालीन नहीं है,वह बहुत गालियां देते हैं। पुरानी पीढ़ी के लिए गाली देना बहुत बुरी बात थी, इसलिए उनको नई पीढ़ी की गालीवाली भाषा बुरी लगती है।कुछ लोग कहते हैं कि जेन जी पेपर लीक के खिलाफ अपने गुस्से को अपने समय और समाज के असंतोष को गाली देकर व्यक्त कर रहे हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि गाली तो हमारे समाज में हमेशा से रही हैं, उसका आविष्कार जेनजी ने नहीं किया है क्योंकि गाली एक विचार नहीं है, अपने भाव की अभिव्यक्ति है।कुछ लोग कहते हैं कि गाली का जवाब कई बार गाली होता है, छोटी गाली का जवाब बड़ी गाली होती है।तब गाली प्रतिरोध का रूप होती है,तब गाली विरोध का रूप होती है, तब गाली बगावत का रूप होती है।जब व्यापक दमन,उत्पीड़न होता है तो वह गाली के विस्फोट के रूप में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि जेनजी ने सड़क पर उतर कर सत्ता को चुनौती दी है और जब देश का विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा था को यह काम जेनजी को जंतर मंतर में उतरकर,सड़क पर उतरकर करना पड़ा। देश में कमजोर विपक्ष,बिखरा हुआ विपक्ष युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, बहुत दिन तक युवाओं ने देखा और जाना कि यह विपक्ष हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता तो वह खुद सीजेपी आंदोलन के जरिए जंतर मंतर व सड़क पर आया। वह जैसा भी है, उसे अब स्वीकारना होगा क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है।जेनजी का आंदोलन कमजोर विपक्ष की विफलता का परिणाम है। विपक्ष इसी तरह कमजोर बना रहा तो आने वाले समय में देश में इसी तरह के और आंदोलन देखने को मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरणों की आहट और कांग्रेस की परीक्षा

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है।राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच संभावित नजदीकियों को लेकर है।हैदराबाद से चलकर हिंदी पट्टी, विशेषकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे ओवैसी ने जिस तरह से अखिलेश यादव को गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है, उसने राज्य के पुराने चुनावी गणित को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है।मुरादाबाद की रैली में ओवैसी का यह कहना कि भाजपा को रोकने के लिए हम समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं, बशर्ते हमें हमारा वाजिब हक मिले, केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है।यह उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के भीतर सुलग रही राजनीतिक आकांक्षाओं और असुरक्षा की भावना को एक नया मंच देने का प्रयास है।

इस पूरे घटनाक्रम ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण की राजनीति को नए सिरे से धार देने का मौका दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर एक बड़ा रणनीतिक संकट खड़ा कर दिया है।इस संकट के केंद्र में सबसे अधिक कोई पार्टी प्रभावित दिख रही है, तो वह कांग्रेस है।पिछले कुछ चुनावों से उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए सपा और ओवैसी के बीच बढ़ती यह नजदीकी एक गहरी असमंजस की स्थिति लेकर आई है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी का हाथ थामेंगे? और यदि ऐसा होता है, या केवल इसकी सुगबुगाहट भी बनी रहती है, तो कांग्रेस इस नए चक्रव्यूह से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी?

असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वे बिना सोचे–समझे कोई बिसात नहीं बिछाते। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20 प्रतिशत है, जो दर्जनों लोकसभा और विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। पारंपरिक रूप से यह मतदाता वर्ग समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की तरफ झुकता रहा है। ओवैसी ने मुरादाबाद की धरती से जो संदेश दिया, वह बहुत साफ था—मुस्लिम समुदाय अब केवल दरी बिछाने और दूसरों को सत्ता तक पहुंचाने का जरिया नहीं बनेगा, उसे सत्ता में आनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए।

ओवैसी का यह रुख अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी राजनीतिक दुविधा पैदा करता है:यदि अखिलेश ओवैसी को पूरी तरह खारिज करते हैं, तो ओवैसी उन पर मुस्लिम विरोधी या मुसलमानों के वोटों का फायदा उठाने वाले नेता का ठप्पा लगाकर अल्पसंख्यक मतों में सेंधमारी कर सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने भले ही खुद ज्यादा सीटें न जीती हों, लेकिन उसने धर्मनिरपेक्ष दलों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है।और यदि अखिलेश यादव ओवैसी से हाथ मिला लेते हैं, तो भाजपा को मुस्लिम तुष्टीकरण और कट्टरपंथ के तुष्टीकरण का नैरेटिव बनाने का सीधा मौका मिल जाएगा। इससे सपा की पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति का गैर–मुस्लिम हिस्सा, विशेषकर पिछड़ी और अगड़ी जातियों का वह वर्ग जो भाजपा से नाराज होकर सपा की तरफ आ सकता है, तुरंत छिटककर वापस भाजपा के पाले में चला जाएगा।अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ओवैसी के साथ मंच साझा करने की एक भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसे उनका पारंपरिक गैर–मुस्लिम वोट बैंक शायद स्वीकार न करे।

इस पूरी सियासी बिसात में कांग्रेस पार्टी सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है।कांग्रेस के सामने यह संकट केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति और इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी पड़ना तय है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के सामने इस समय तीन बड़ी चुनौतियां हैं:

पहली कांग्रेस खुद को देश की सबसे बड़ी और स्वाभाविक धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है। उत्तर प्रदेश में वह सपा के साथ गठबंधन में रहकर खुद को अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में पेश करती रही है।लेकिन अगर ओवैसी इस त्रिकोण में प्रवेश करते हैं, तो वे कांग्रेस के इस नैरेटिव को सीधे चुनौती देंगे। ओवैसी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि उसने दशकों तक मुसलमानों का केवल इस्तेमाल किया और उन्हें नेतृत्व नहीं दिया।कांग्रेस के लिए ओवैसी के इस तीखे वैचारिक हमले का जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी सीधे जमीनी मुद्दों और आंकड़ों के साथ बात करते हैं।

दूसरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की छोटे भाई वाली भूमिका से बाहर निकलकर अपनी सीटों की संख्या और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहती है।यदि सपा और ओवैसी के बीच कोई परोक्ष या अपरोक्ष समझौता होता है, तो गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे का गणित पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ओवैसी निश्चित रूप से उन सीटों पर दावा ठोकेंगे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है—जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड का इलाका। इत्तेफाक से, कांग्रेस भी इन्हीं क्षेत्रों में अपने पुराने आधार को पुनर्जीवित करने की उम्मीद लगाए बैठी है।ऐसे में ओवैसी का आना कांग्रेस के हिस्से की सीटों में कटौती कर सकता है।

तीसरी कांग्रेस की राष्ट्रीय रणनीति इस समय सॉफ्ट–हिंदुत्व, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के इर्द–गिर्द घूम रही है।वह बहुसंख्यक समाज के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ना चाहती है।लेकिन अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ओवैसी और सपा की दोस्ती की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, तो भाजपा पूरे चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण के ध्रुवों पर केंद्रित कर देगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, जिससे कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

ऐसी हालात में कांग्रेस समाजवादी पार्टी नेतृत्व को यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करेगी कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए ओवैसी जैसे तत्वों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।कांग्रेस का तर्क होगा कि ओवैसी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन पूरे देश में गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। वह अखिलेश यादव को यह याद दिलाएगी कि अगर वे उत्तर प्रदेश के बाहर (जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार में) एक गंभीर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और सर्वसमावेशी ढांचे के साथ चलना होगा, न कि किसी क्षेत्रीय या समुदाय–विशेष की राजनीति करने वाले दल के साथ।

केवल ओवैसी की आलोचना करने से कांग्रेस का काम नहीं चलेगा।उसे मुस्लिम समाज के भीतर ओवैसी के प्रति बढ़ते आकर्षण को रोकना होगा।इसके लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग, धर्मगुरुओं और युवाओं के बीच सीधे जाकर यह संदेश देने की योजना बना रही है कि देश के स्तर पर भाजपा का मुकाबला केवल कांग्रेस ही कर सकती है, कोई क्षेत्रीय दल नहीं। कांग्रेस अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखेगी और यह साबित करने की कोशिश करेगी कि भावुक बयानों के बजाय व्यावहारिक राजनीति ही उनका भला कर सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पर्दे के पीछे भाजपा इस पूरी हलचल पर पैनी नजर रखे हुए है। भाजपा के लिए ओवैसी और अखिलेश की दोस्ती की आहट भी एक बड़े सियासी वरदान जैसी है। भाजपा इस स्थिति का उपयोग अपने मुख्य एजेंडे को धार देने के लिए करेगी।तब भाजपा जनता के बीच यह संदेश ले जाने में तनिक भी देर नहीं करेगी कि सत्ता पाने के लिए सपा और कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि ओवैसी जैसी राजनीति का समर्थन भी कर सकते और यदि ओवैसी अलग चुनाव लड़ते हैं, तो वे विपक्ष के वोट काटेंगे; यदि वे सपा के साथ आते हैं, तो बहुसंख्यक वोट एकजुट होकर भाजपा की तरफ आएंगे।दोनों ही सूरतों में भाजपा के लिए यह विन–विन यानी हर हाल में फायदे वाली स्थिति बनती दिख रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का मार्ग तय करती आई है। ओवैसी द्वारा अखिलेश यादव की तरफ बढ़ाया गया हाथ और उस पर कांग्रेस की चिंताएं यह दर्शाती हैं कि राज्य में चुनावी जंग अब केवल विकास या जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं रह गई है। यह विचारधाराओं, पहचान की राजनीति और रणनीतिक वर्चस्व की एक बेहद पेचीदा लड़ाई बन चुकी है।

कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर ठोस फैसले लेने का है।उसे यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मतदाता अब केवल भाजपा के डर से किसी को वोट देने के मूड में नहीं है, वह अपनी राजनीतिक पहचान और सम्मान चाहता है। ओवैसी इसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।यदि कांग्रेस ओवैसी के इस उभार को रोकने में नाकाम रहती है, या अखिलेश यादव को एक आत्मघाती कदम उठाने से नहीं रोक पाती, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का भविष्य संकट में पड़ सकता है। आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि कांग्रेस इस राजनीतिक बिसात पर शह और मात के खेल में खुद को किंगमेकर के रूप में स्थापित रख पाती है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के हाशिये पर धकेल दी जाती है।

आरबीआई का निर्णय : सुरक्षित और टिकाऊ मुद्रा की नई पहल

महेन्द्र तिवारी

भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रही है।डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन के बावजूद नकद मुद्रा आज भी करोड़ों भारतीयों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।देश के छोटे व्यापार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, कृषि बाजार और असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आज भी नकद लेनदेन पर निर्भर है।ऐसे में मुद्रा की गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊपन केवल तकनीकी विषय नहीं रह जाते, बल्कि आर्थिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से सीधे जुड़े होते हैं।इसी संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पॉलीमर अर्थात प्लास्टिक आधारित नोटों की दिशा में उठाया गया कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।केंद्र सरकार ने आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दस रुपये और बीस रुपये के पॉलीमर नोटों के बड़े पैमाने पर फील्ड ट्रायल की अनुमति दी है।पहले चरण में दोनों मूल्यवर्ग के एक एक अरब नोटों का परीक्षण किया जाएगा।यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो भविष्य में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में भी इस तकनीक का विस्तार किया जा सकता है।फिलहाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि कागजी नोटों को तत्काल हटाने की कोई योजना नहीं है और यह केवल परीक्षण आधारित पहल है।

पॉलीमर नोट सामान्य कागज से नहीं बल्कि विशेष प्रकार के सिंथेटिक पॉलीमर पदार्थ से बनाए जाते हैं।यह सामग्री नमी, धूल, गंदगी और बार बार मोड़े जाने जैसी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से सहन कर सकती है।यही कारण है कि इनकी आयु पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। सामान्यतः कम मूल्यवर्ग के नोट सबसे अधिक हाथों से गुजरते हैं और कुछ ही महीनों में फटने या खराब होने लगते हैं।इसके कारण रिजर्व बैंक को हर वर्ष बड़ी संख्या में पुराने नोट वापस लेकर नए नोट छापने पड़ते हैं।यदि पॉलीमर नोट अपेक्षा के अनुसार लंबे समय तक चलते हैं तो नोटों की छपाई, परिवहन और नष्ट करने की लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

भारत में नकली नोटों की चुनौती लंबे समय से चिंता का विषय रही है। समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों ने नकली भारतीय मुद्रा के नेटवर्क का खुलासा किया है। नकली नोट केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनका उपयोग अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध में भी किया जाता है। पॉलीमर नोटों में पारदर्शी विंडो, उन्नत होलोग्राम, रंग बदलने वाली स्याही, सूक्ष्म प्रिंटिंग और अन्य आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं। इन विशेषताओं की नकल करना पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में कहीं अधिक कठिन माना जाता है। इसलिए पॉलीमर नोट नकली मुद्रा पर प्रभावी नियंत्रण का माध्यम बन सकते हैं।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। पहली नजर में प्लास्टिक शब्द सुनकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं स्वाभाविक लग सकती हैं, लेकिन पॉलीमर नोट सामान्य प्लास्टिक नहीं होते।इनका निर्माण विशेष तकनीक से किया जाता है और उपयोग के बाद इन्हें पुनर्चक्रित भी किया जा सकता है।चूंकि इनकी आयु अधिक होती है इसलिए समान अवधि में कम संख्या में नोट छापने पड़ते हैं। इससे कागज की खपत, ऊर्जा की आवश्यकता और परिवहन संबंधी खर्च में भी कमी आती है।कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी माना है कि लंबे समय में पॉलीमर नोट पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

दुनिया के अनेक देशों ने पहले ही पॉलीमर मुद्रा को अपनाकर इसके लाभ प्राप्त किए हैं। ऑस्ट्रेलिया इस तकनीक को अपनाने वाला पहला देश था।इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया और अनेक अन्य देशों ने भी अपनी मुद्रा में पॉलीमर तकनीक का उपयोग किया।इन देशों के अनुभव बताते हैं कि पॉलीमर नोट अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं और नकली नोटों की घटनाओं में कमी लाने में सहायक होते हैं।भारत जैसे विशाल देश के लिए इन अनुभवों का अध्ययन अत्यंत उपयोगी हो सकता है।

भारत में पॉलीमर नोटों का विचार नया नहीं है। वर्ष 2013 और उसके बाद भी सीमित स्तर पर कुछ शहरों में इनका परीक्षण किया गया था। उस समय विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी।अब बदलती आर्थिक आवश्यकताओं, बेहतर तकनीक और बढ़ती मुद्रा मांग को देखते हुए इसे नए रूप में पुनर्जीवित किया गया है।इस बार परीक्षण का दायरा पहले की तुलना में कहीं बड़ा रखा गया है ताकि अलग अलग जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों और उपयोग के स्तर पर नोटों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके।

भारत जैसे देश में मौसम की विविधता एक बड़ी चुनौती है।कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो कहीं लगातार वर्षा होती है। कई क्षेत्रों में धूल और नमी का स्तर भी अधिक रहता है।ऐसे वातावरण में कागजी नोट अपेक्षाकृत जल्दी खराब हो जाते हैं।फील्ड ट्रायल का उद्देश्य यही समझना है कि पॉलीमर नोट वास्तविक परिस्थितियों में कितने प्रभावी सिद्ध होते हैं। यदि वे इन परिस्थितियों में भी अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हैं तो उनका व्यापक उपयोग आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो सकता है।

हालांकि इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पॉलीमर नोटों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कागजी नोटों की तुलना में अधिक होती है। इसके अलावा एटीएम मशीनों, नकदी गिनने वाली मशीनों और बैंकिंग प्रणाली के कुछ उपकरणों में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं।जनता को नए नोटों की विशेषताओं की जानकारी देना और उन्हें नकली नोटों से अलग पहचानने का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक होगा।इसलिए यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से विकसित हुई है।यूपीआई ने लेनदेन की दुनिया बदल दी है, फिर भी नकदी की उपयोगिता समाप्त नहीं हुई है। छोटे दुकानदारों, ग्रामीण क्षेत्रों, सीमित इंटरनेट वाले इलाकों और अनेक सामाजिक परिस्थितियों में नकद भुगतान आज भी सबसे सुविधाजनक माध्यम है। इसलिए डिजिटल अर्थव्यवस्था और नकद मुद्रा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पॉलीमर नोटों की पहल इसी संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें आधुनिक तकनीक अपनाते हुए नकद मुद्रा को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा रहा है।

आरबीआई का यह निर्णय केवल नए प्रकार के नोट जारी करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह भविष्य की मुद्रा व्यवस्था की दिशा भी तय करता है।यदि परीक्षण सफल रहता है तो भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन्होंने आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपनी मुद्रा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाया है। इससे जनता का विश्वास मजबूत होगा, नकली नोटों की चुनौती कम होगी और मुद्रा प्रबंधन की लागत में भी दीर्घकालिक बचत संभव होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कागजी नोटों को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।परीक्षण पूरा होने के बाद उसके परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि अपेक्षित सफलता मिलती है तभी आगे की रणनीति तय होगी।यह सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत की विशाल आबादी और विविध परिस्थितियों में किसी भी बड़े परिवर्तन को चरणबद्ध तरीके से लागू करना ही व्यावहारिक होता है।

आर्थिक सुधारों की सफलता केवल नई नीतियां बनाने से नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से निर्धारित होती है। पॉलीमर नोटों का प्रयोग भी इसी कसौटी पर परखा जाएगा। यदि यह पहल सफल होती है तो भारत की मुद्रा व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बन सकती है।इससे नकली नोटों पर नियंत्रण, सरकारी खर्च में कमी, जनता को बेहतर गुणवत्ता वाले नोट और बैंकिंग व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाने जैसे अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आने वाले वर्षों में यह पहल भारतीय मुद्रा इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक सिद्ध हो सकती है और यह दिखाएगी कि तकनीकी नवाचार किस प्रकार आम नागरिक के दैनिक जीवन को भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकता है।

कॉकरोच आंदोलन : गांधीवाद की छाया या डिजिटल युग का नया प्रतिरोध?

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में जब भी कोई नया जन–आंदोलन उभरता है, उसे पुराने वैचारिक फ्रेमों में समझने की कोशिश होती है।कॉकरोच आंदोलन के साथ भी यही हुआ है।कुछ लोग इसे युवाओं के असंतोष की नई अभिव्यक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे गांधीवादी परंपरा की छाया में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।किंतु प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इस आंदोलन को महात्मा गांधी की प्रसंगिकता से जोड़ा जा सकता है, या यह केवल एक आकर्षक किंतु सतही तुलना है?

इस प्रश्न का उत्तर न तो पूर्णतः हाँ है और न ही नहीं। कॉकरोच आंदोलन में गांधीवादी राजनीति के कुछ तत्व अवश्य दिखाई देते हैं, किंतु उसका स्वभाव, भाषा, माध्यम और वैचारिक संरचना गांधीवाद से स्पष्ट रूप से भिन्न है। इसलिए इसे गांधीजी की परंपरा का सीधा विस्तार मानने से पहले उसकी प्रकृति और सीमाओं को समझना आवश्यक है। गांधीवादी राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति उसका नैतिक अनुशासन था। सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, जनसेवा और रचनात्मक कार्यक्रम—ये केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, बल्कि आंदोलन की आत्मा थे।गांधी के लिए संघर्ष का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि व्यक्ति और समाज के नैतिक रूपांतरण की प्रक्रिया भी था। इसी कारण उनके आंदोलन में साधन और साध्य के बीच गहरा सामंजस्य दिखाई देता है।

इसके विपरीत, कॉकरोच आंदोलन की शक्ति उसकी व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता और डिजिटल सक्रियता में निहित है।यह ऐसे दौर में सामने आया है, जब नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक भाषाओं से दूरी बना रही है और सोशल मीडिया, मीम, डिजिटल अभियानों तथा सार्वजनिक प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी असहमति दर्ज करा रही है।यह आंदोलन दर्शाता है कि आज का युवा अपने असंतोष को पुराने राजनीतिक ढाँचों के बजाय नए सांस्कृतिक प्रतीकों और संचार माध्यमों के जरिए व्यक्त करना चाहता है। इस दृष्टि से यह समकालीन प्रतिरोध की नई शैली है, पारंपरिक सत्याग्रह का पुनरावर्तन नहीं।

फिर भी गांधीवादी प्रसंग से इसका संबंध पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता।गांधीजी ने राजनीति के केंद्र में सामान्य नागरिक को स्थापित किया था।उन्होंने यह विश्वास जगाया कि किसी भी परिवर्तन की वास्तविक शक्ति जनता की चेतना, उसके श्रम और उसके नैतिक साहस में निहित होती है। कॉकरोच आंदोलन भी इस अर्थ में महत्त्वपूर्ण है कि उसने युवाओं की बेरोजगारी, परीक्षा–प्रणाली की विश्वसनीयता, संस्थागत जवाबदेही और शासन के प्रति बढ़ते अविश्वास जैसे प्रश्नों को सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला दिया।इस स्तर पर यह जन–भागीदारी की वही ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे गांधीवादी राजनीति का मूल तत्व माना जाता है।

किन्तु यहीं सबसे महत्वपूर्ण अंतर भी सामने आता है। गांधी के लिए साधनों की पवित्रता सर्वोपरि थी। उनका विश्वास था कि अनुचित साधनों से उचित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, कॉकरोच आंदोलन का स्वर अधिक तीखा, व्यंग्यप्रधान और तात्कालिक है।वह व्यवस्था को चुनौती तो देता है, किंतु गांधी की तरह आत्मानुशासन, आत्मबल और वैचारिक संयम पर उतना बल नहीं देता। उसकी भाषा प्रतिरोध की भाषा है, तपस्या की नहीं।इसलिए उसे पूर्णतः गांधीवादी कहना उसकी अपनी विशिष्ट पहचान को धुंधला कर देता है।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि गांधीवाद केवल विरोध की राजनीति नहीं था।वह ग्राम–स्वराज, स्वदेशी, श्रम की गरिमा, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव और रचनात्मक राष्ट्र–निर्माण की व्यापक अवधारणा था।इसके विपरीत, कॉकरोच आंदोलन का वतर्मान फोकस मुख्यतः शिक्षा, रोजगार, युवाओं की आकांक्षाओं और संस्थागत उत्तरदायित्व तक सीमित दिखाई देता है। इसलिए इसे गांधीवाद जैसी व्यापक सामाजिक परियोजना कहना अभी जल्दबाजी होगी।

फिर भी दोनों के बीच एक गहरी समानता अवश्य है—दोनों जनता की चुप्पी को तोड़ते हैं। गांधी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सामान्य भारतीय को बोलना सिखाया था। आज का यह आंदोलन युवाओं को यह विश्वास दिलाता है कि असंतोष केवल निजी निराशा नहीं है; उसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति भी दी जा सकती है। जब युवाओं की समस्याएँ डिजिटल मंचों, सार्वजनिक प्रदर्शनों और सामाजिक संवाद के माध्यम से सामने आती हैं, तब यह लोकतंत्र की जीवंतता का संकेत होता है।राजनीति समाप्त नहीं हुई है; उसने केवल अपने नए माध्यम और नए प्रतीक खोज लिए हैं।

इसलिए गांधीजी की प्रसंगिकता यहाँ प्रत्यक्ष प्रेरणा के रूप में कम और एक नैतिक कसौटी के रूप में अधिक महत्त्वपूर्ण है।प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कॉकरोच आंदोलन गांधीवादी है या नहीं; बल्कि यह होना चाहिए कि क्या यह आंदोलन जनता की नैतिक चेतना को जागृत करता है? क्या यह केवल क्षणिक असंतोष का विस्फोट है या किसी दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन की भूमिका तैयार कर रहा है? क्या इसकी व्यंग्यात्मक शक्ति लोकतांत्रिक सुधारों में परिवर्तित हो पाएगी?

इन प्रश्नों के उत्तर समय देगा। अभी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस आंदोलन को गांधीजी से जोड़ना आंशिक रूप से उचित है, यदि हम इसे जन–भागीदारी, नागरिक असहमति और जवाबदेही की मांग के संदर्भ में देखें।किंतु यदि इसे सत्याग्रह, अहिंसा, आत्मसंयम और नैतिक पुनर्निर्माण की कसौटी पर परखा जाए, तो यह गांधीवाद से अलग दिखाई देता है। यह गांधी का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि डिजिटल युग की नई विरोध–संस्कृति का प्रतिनिधि है।

किसी भी जन–आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसके प्रतीकों या लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य, साधनों, नैतिकता और दीर्घकालिक प्रभाव से किया जाना चाहिए।यदि कोई आंदोलन जनता को जागरूक करता है, सत्ता से जवाबदेही मांगता है और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करता है, तो वह गांधीवादी विरासत के कुछ तत्वों को स्पर्श अवश्य करता है। किंतु यदि उसमें सत्य, अहिंसा, आत्मानुशासन और रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन की व्यापक दृष्टि का अभाव है, तो उसे गांधीवाद का विस्तार कहना उचित नहीं होगा। इसलिए तथाकथित ‎ह्लकॉकरोच आंदोलनह्व को गांधीवाद का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि डिजिटल युग की नई विरोध–संस्कृति के रूप में समझना अधिक समीचीन होगा।इतिहास अंततः यही तय करेगा कि यह क्षणिक असंतोष था या लोकतांत्रिक चेतना का एक स्थायी अध्याय।

बाबा बैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर दुर्ग से भक्तों का पहला जत्था हुआ रवाना

दुर्ग रेलवे स्टेशन से करीब 200 शिवभक्तों का जत्था विशेष ट्रेन द्वारा हुआ प्रस्थान, बोलबम की गूंज से गूंज उठा दुर्ग स्टेशन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

सावन के पहले दिन बैद्यनाथ धाम के लिए ट्रेन से रवाना हुआ कांवरियों का जत्था, बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हुआ स्टेशन, सावन के पहले दिन से ही बोल बम के जयघोष गूंजने लगे. देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए पूरे प्रदेश से आज हजारों श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए सुल्तानगंज की ओर रवाना हुए. भीड़ को देखते हुए रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ ने विशेष इंतजाम किए हैं. सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही देशभर में शिवभक्ति का रंग चढ़ गया है. झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का सैलाब भी निकल पड़ा, दुर्ग पर पहले ही दिन हजारों शिवभक्त जुटे. पूरा स्टेशन में बोलबम सेवा समिति गंजपारा के शिव भक्तों के बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा. कंधों पर कांवड़, होते दिखाई दिए.

भगवा वस्त्र और चेहरे पर भक्ति का उत्साह लिए श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए सुल्तानगंज की ओर रवाना

सावन माह की पवित्रता और आस्था के साथ आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से आज बोलबम सेवा समिति गंजपारा के करीब 200 शिवभक्तों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) की यात्रा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं को गजेन्द्र यादव केबिनेट मंत्री ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर पूर्व विधायक अरुण वोरा महापौर श्रीमती अलका बाघमार सभापति नगर निगम सभापति श्याम शर्मा पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल एवं पूर्व महापौर आर एन वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया।

बोलबम सेवा समिति के मनोज गुप्ता लाला एवं सुरेश गुप्ता ने बताया कि यात्रा पर रवाना हो रहे श्रद्धालुओं को गजेन्द्र यादव ने पुष्पगुच्छ देकर एवं अरुण वोरा ने शहर एवं प्रदेश देश की खुशहाली के लिए बैजनाथ धाम में बाबा का त्रिशूल चढ़ाने हेतु बोलबम सेवा समिति के सदस्यों को भेट किया, सभी उपस्थित जनों ने पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया तथा उनकी सुरक्षित और मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएँ दी गई। स्टेशन परिसर ह्वबोल बमह्व हर हर महादेवह्व जैसे जयघोषों से गूंज उठा।

गजेन्द्र यादव ने इस यात्रा पर कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राएं न केवल हमारी आस्था को प्रबल करती हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करती हैं।

अरुण वोरा ने कहा कि बाबा धाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि सामूहिक एकता, अनुशासन और संस्कृति का भी प्रतीक है। इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति भावना का संचार करते हैं।

ललित चंद्राकर ने कहा कि यह यात्रा हमारी श्रद्धा, संस्कृति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। बाबा भोलेनाथ सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय करें।

यात्रा में जा रहे शिवभक्तों में एक ऐसा शिव भक्त प्रकाश ठाकुर जो मेडिकल दुकान चलाता है उसने सभी शिव भक्तों के लिए सभी प्रकार की दवाई दर्द का लोशन एवं हर प्रकार का उपयोगी पावडर अपने साथ रखा जो कि सभी को निःशुल्क वितरण किया करेगा जिसकी प्रशंसा सभी ने की। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह जत्था विशेष रेलगाड़ी से देवघर के लिए रवाना हुआ, जहां भक्तजन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक करेंगे।

बाबाधाम जा रहे शिवभक्तों को शुभकामनाएं सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर के संरक्षक अजय शर्मा नवल अग्रवाल जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष रवि पीडियार रायसिंह ढ़िकोला फत्ते भाटिया शिव नायक विवेक मिश्रा गुरदीप भाटिया विकाश पुरोहित राहुल शर्मा सतबीर शर्मा ऋषि साहू सुजल शर्मा भार्गव चक्रधारी शिबू मिर्जा सुधीर कुमार दिनेश शर्मा राकेश महोबिया सुजल शर्मा एवं सैकड़ों शिव भक्त उपस्थित थे

खास खबर

जिला हॉकी संघ राजनांदगांव : फिरोज अंसारी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित, अन्य पदों के लिए 31 जुलाई को होगी नाम वापसी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिला हॉकी संघ राजनांदगांव के नवीन कायर्कारिणी के गठन के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को पूर्ण हो गई। म्युनिसिपल स्कूल ग्राउंड स्थित छत्तीसगढ़ हॉकी संघ कार्यालय में पूर्वान्ह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नामांकन लिए गए।

फिरोज अंसारी बनेंगे अध्यक्ष : निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता गुणेंद्र साव एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी सुधांशु जोशी व प्रवीण चंद्रवंशी की उपस्थिति में हुई नामांकन प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए केवल फिरोज अंसारी का ही नामांकन प्राप्त हुआ। अन्य किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके कारण श्री अंसारी निविरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए।

अन्य पदों पर मुकाबला संभव : अन्य पदों के लिए कुल 18 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उपाध्यक्ष - 04 पदः भूषण लाल साव, आशा थॉमस, शिवनारायण धकेता, दौलत सिंह चंदेल - कुल 04 नामांकन, सचिव - 01 पदः शिवनारायण धकेता, वीरेंद्र सिंह भाटिया - 02 नामांकन , सह-सचिव - 04 पदः महेंद्र सिंह ठाकुर, बबिता लिल्हारे, अनुराज श्रीवास्तव, गुणवंत पटेल - 04 नामांकन, कोषाध्यक्ष - 01 पदः वीरेंद्र सिंह भाटिया - 01 नामांकन, कार्यकारिणी सदस्य - 05 पदः कुमार स्वामी, गुणवंत पटेल, गणेश प्रसाद शर्मा, शबनम बानो, संदीप सिंह ग्रेवाल, खुशाल यादव - 06 नामांकन हैं। जानकारी के अनुसार भूषण साव, दौलत चंदेल उपाध्यक्ष, तथा आशा थॉमस, गणेश शर्मा, कुमार स्वामी, हनी ग्रेवाल कायर्कारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं।

आज नाम वापसी : निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 31 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद अंतिम प्रत्याशी सूची जारी कर मतदान की तिथि तय की जाएगी।

विधायक रिकेश सेन ने गुरु पूणिर्मा पर पंडित विजयकांत भट्ट से लिया आशीर्वाद

भिलाई। गुरु पूणिर्मा के अवसर पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पं. विजयकांत भट्ट के सेक्टर-2 स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने पं. भट्ट व उनकी सहधर्मिणी का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया। विधायक रिकेश ने पं. भट्ट के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। पं. भट्ट ने विधायक रिकेश के सुखद भविष्य की कामना की।

दुर्ग जिला अस्पताल में बनेगा आधुनिक सर्जिकल विंग, मंत्री शिक्षा गजेन्द्र यादव ने किया भूमिपूजन

485 .43 लाख की लागत से बनने वाले सर्जिकल विंग होंगी कई सुविधाएं

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग जिला चिकित्सालय परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज सर्जिकल विंग के प्रथम तल (फेज-2) के निर्माण कार्य का भूमिपूजन शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव द्वारा किया गया। लगभग 485.43 लाख की लागत से बनने वाला यह आधुनिक सर्जिकल विंग जिला चिकित्सालय की उपचार क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा तथा दुर्ग सहित आसपास के जिलों से आने वाले हजारों मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सरकार की सवोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ जिला चिकित्सालयों का उन्नयन, नए भवनों का निर्माण तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि दुर्ग जिला चिकित्सालय लंबे समय से बड़ी संख्या में मरीजों को उपचार उपलब्ध करा रहा है। बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए इस आधुनिक सर्जिकल विंग का निर्माण अत्यंत आवश्यक था। इसके पूर्ण होने के बाद मरीजों को बेहतर उपचार, आधुनिक सुविधाएं तथा चिकित्सकों को अधिक सुव्यवस्थित कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। इससे गंभीर मरीजों के उपचार में भी काफी सुविधा मिलेगी और जिला चिकित्सालय की सेवाएं पहले से अधिक प्रभावी बनेंगी।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने, विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था करने तथा आमजन को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आने वाले समय में भी दुर्ग जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सभी कार्य प्राथमिकता के साथ किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि दुर्ग शहर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। पूर्व में भी उनकी पहल पर जिला चिकित्सालय में अनेक विकास एवं उन्नयन कार्य स्वीकृत हुए हैं और भविष्य में भी अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है ताकि सभी बीमारी का उपचार यही हो सके।

5 वार्ड, 78 बेड, 7 प्राइवेट रूम और दो लिफ्ट की सुविधा : निर्माण एजेंसी के अभियंताओं ने बताया कि आधुनिक सर्जिकल विंग के प्रथम तल पर कुल 5 वार्ड विकसित किए जाएंगे, जिनमें 78 मरीजों के लिए बेड उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त 7 प्राइवेट रूम भी बनाए जाएंगे, जिससे मरीजों को सुविधाजनक उपचार मिल सके। मरीजों के परिजनों के लिए महिला एवं पुरुषों के अलग-अलग प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। भवन में आवागमन की सुविधा के लिए दो आधुनिक लिफ्ट, पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। आधुनिक डिजाइन के अनुरूप तैयार होने वाला यह भवन मरीजों और चिकित्सकों दोनों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा।

भूमिपूजन कार्यक्रम में राज्य तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जीतेन्द्र साहू, सभापति श्याम शर्मा, पार्षदगण, मंडल अध्यक्षगण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी, कार्यपालन अभियंता श्री भट्टाचार्य, चिकित्सकगण, जीवन दीप समिति के सदस्य, विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शिक्षा से जोड़ना सबसे बड़ा पुण्य कार्य - एसएसपी विजय अग्रवाल

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शिव जी अर्पण सेवा समिति, भिलाई नगर ने सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश करते हुए शासकीय उच्च प्राथमिक शाला, धनोरा के 26 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। समिति ने इन बच्चों को सालभर की आवश्यक शिक्षण सामग्री भेंट कर उनकी पढ़ाई की राह आसान की। गोद लिए गए बच्चे या तो अनाथ हैं या उन्होंने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है।

स्कूल बैग से लेकर छतरी तक दी सामग्री : आयोजन में बच्चों को पढ़ाई के लिए निम्न सामग्री दी गईः स्कूल बैग, 7 नोटबुक, जूते-मोजे, लंच बॉक्स, वॉटर बॉटल, पेन का डिब्बा और बारिश से बचाव के लिए छतरी। समिति का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण इन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।

SSP विजय अग्रवाल ने की सराहना : कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने समिति की पहल की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि "माता-पिता के साये से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना समाज का सबसे बड़ा पुण्य कार्य है।" इस अवसर पर ग्राम धनोरा की सरपंच और स्कूल की प्राचार्य ने भी समिति के प्रति आभार जताया। दोनों ने कहा कि यह पहल बच्चों के भविष्य के लिए बेहद मददगार और प्रेरणादायी है।

आगे भी जारी रहेगी मदद : शिव जी अर्पण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। समिति आगे भी इस तरह के सेवा कार्यों के लिए तत्पर रहेगी। कार्यक्रम में समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, स्कूल स्टाफ और ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

"पानी सहेजने महिलाओं को आना होगा सामने" - उप अभियंता डिगेश्वरी चंद्राकर

नगर निगम रिसाली में "कैच द रेन" पर हुई संगोष्ठी

नई दृष्टिबिंदु / रिसाली-भिलाई

नगर पालिक निगम, रिसाली द्वारा "कैच द रेन" अभियान के तहत जल संरक्षण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। निगम आयुक्त मोनिका वर्मा के निर्देश पर आयोजित इस संगोष्ठी में क्षेत्र की महिलाओं को बारिश के पानी को सहेजने और उपयोग करने की जानकारी दी गई।

भूमिगत जल स्तर बढ़ाने पर जोर

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उप अभियंता डिगेश्वरी चंद्राकर ने कहा कि जल बचाने और उसे संरक्षित करने में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि "पानी का सर्वाधिक उपयोग महिलाएं करती हैं, इसलिए भविष्य में होने वाले जल अभाव से निपटने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा।" कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बारिश के पानी को संग्रहित कर भूमिगत जल स्रोतों को बढ़ाना है।

महिलाओं ने चलाने का किया संकल्प

संगोष्ठी में उपस्थित महिलाओं ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य को देखते हुए अपने

आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगी। कार्यक्रम में वूमेन फॉर ट्री से जुड़ी महिलाएं एवं स्व सहायता समूह की सदस्याएं शामिल हुईं।

इस तरह बचाएं जल

उप अभियंता ने जल संरक्षण के लिए 5 सरल उपाय बताएःबारिश के पानी को पात्रों में एकत्र कर निस्तारी कार्यों में उपयोग करें। बारिश के साफ जल को पाइप के माध्यम से बोर व कुएं में संग्रहित करें। घर के आसपास सोक पिट बनाएं ताकि भूमिगत जल स्तर बढ़ सके। अधिक से अधिक खाली जगहों पर पौधारोपण करें। जल संरक्षण के लिए आमजनों को प्रोत्साहित करें।

धर्मसभा

दुर्ग में धर्म सभा और चातुर्मास प्रारंभ, गुरु पूणिर्मा पर दिए प्रवचन

राष्ट्रसंत मणिभद्र मुनिः "श्रद्धा की नहीं, सत्य की चिंता करो"

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राष्ट्रसंत मानव मिलन संस्थापक डॉ. मणिभद्र मुनि जी ने कहा कि श्रद्धा तभी सार्थक है जब उसकी जड़ में सत्य हो। भय या मान्यता से उत्पन्न श्रद्धा मिथ्या है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि "श्रद्धा की चिंता छोड़ो, सत्य का अनुसंधान करो।" राष्ट्रसंत ने यह प्रवचन जय आनंद मधुकर रतन भवन, बांधा तालाब, दुर्ग में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए दिए। धर्म सभा का संचालन टीकम छाजेड़ ने किया।

सम्यक श्रद्धा की परिभाषा : मुनि श्री ने कहा कि "श्रद्धा का अर्थ है वह भावदशा जो सत्य से सृजित हुई है। सत्य के गर्भ से जन्मी श्रद्धा अटूट और अटल होती है। उसे कोई छीन नहीं सकता और न विचलित कर सकता है।" भगवान महावीर ने इसे सम्यक श्रद्धा कहा है। इसके विपरीत जो श्रद्धा मान्यता से जन्मी है वह मिथ्या श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि भय भी श्रद्धा का एक कारण बनता है - नरक का भय, दुख का भय। लेकिन सच्ची श्रद्धा केवल सत्य पर आधारित होती है।

नवकार महामंत्र जाप और पारणा : धर्म सभा के साथ नवकार महामंत्र जप अनुष्ठान भी प्रारंभ हो गया है। आज के जाप का लाभ वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक श्रमण संघ के अध्यक्ष धर्मचंद लोढ़ा परिवार ने लिया। कल सम्पन्न हुई तपस्या का पारणा जय आनंद मधुकर रतन भवन की भोजनशाला में संपन्न हुआ। राष्ट्रसंत मणिभद्र मुनि के दर्शन-वंदन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से गुरु भक्त परिवार दुर्ग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए प्रचार प्रसार प्रमुख नवीन संचेती ने बताया कि प्रवचन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

साधुमार्गी जैन संघ का चातुर्मास प्रारंभ : प्रणत मुनि और मनीष मुनि के सानिध्य में तपस्या शुरू। इसी बीच साधुमार्गी जैन संघ, दुर्ग में भी चातुर्मास का शुभारंभ हो गया है। दीक्षा के दुर्ग नगर में प्रणत मुनि सागरमल गुलाबचंद सांखला और उनके गुरु भाई मनीष मुनि समता भवन, दुर्ग में भाव-भक्ति के साथ चातुर्मास प्रारंभ किया। गुरु पूणिर्मा पर अपने भाव व्यक्त करते हुए मुनि महाराज ने कहा कि "गुरु के उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कंकर से शंकर और आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग गुरु भगवंत ही दिखाते हैं। जिस प्रकार पूणिर्मा का चांद पूरे आभामंडल को प्रकाशित करता है, उसी तरह सद्गुरु का ज्ञान जीवन यात्रा को प्रकाशित कर सही दिशा देता है।"

मनीष मुनि एवं प्रणत मुनि के सानिध्य में त्याग-तपस्या की लड़ी भी शुरू हो चुकी है। इसमें मीठालाल जी संचेती, गौरव जी पारख, चंचल जी सांखला, वीणा जी श्रीश्रीमाल की तपस्या प्रारंभ है। इस वर्ष साधुमार्गी संघ को चतुर्विध संघ का सानिध्य प्राप्त होने से पूरे संघ में हर्ष का माहौल है। संघ अध्यक्ष ओमप्रकाश सांखला और मंत्री गौतम पारख ने संघ के सभी वर्गों से बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप बोथरा ने किया।

मोहला बना भू-माफियाओं का हबः प्रतिबंध के बाद भी कृषि भूमि की धड़ल्ले से हो रही रजिस्ट्री

चिलमटोला में 7 एकड़ कृषि भूमि के 40 टुकड़े, राजस्व विभाग और रजिस्ट्री कार्यालय पर उठे सवाल

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

जिला मुख्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में भू-माफियाओं ने कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग का गोरखधंधा शुरू कर दिया है। आदिवासी अनुसूचित जनजाति जिले में छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग और रेरा के नियम-कानून को ताक पर रखकर कृषि भूमि के टुकड़े कर महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि इस अवैध काम में स्थानीय राजस्व विभाग और उप पंजीयक कार्यालय का भी पूरा सहयोग मिल रहा है।

चिलमटोला बना अवैध प्लाटिंग का केंद्रः जिले में सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम चिलमटोला की हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मोहला की सीमा से लगे इस गांव में बांध और मुक्ति धाम से सटी लगभग 7 एकड़ से अधिक कृषि भूमि को बिना डायवर्सन के ही आवासीय प्लाट के रूप में काटकर बेचा जा रहा है। भू-माफियाओं ने एक के बाद एक लगे 5 कृषि भूमि खसरों को 40 से अधिक टुकड़ों में बांट दिया है। राजस्व विभाग और पंजीयक कार्यालय के अधिकारी रजिस्ट्री और नामांतरण करने में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। इससे शासन को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है।

कौन हैं मुख्य आरोपी ? : ग्रामीणों के अनुसार जिस भूमि की अवैध प्लाटिंग हो रही है वह राजस्व रिकॉर्ड में अफरोज खान, सजीदा बेगम, शहनाज बेगम, सायरा बेगम, हेमंत साहू, मोहन के नाम दर्ज है। इसे भू-माफिया रेमंत देवांगन और हेमंत साहू ने हुंडी में खरीदकर अब आम लोगों को मोटी कीमत पर बेचना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि रेमंत देवांगन पहले भी आदिवासी परिवार से फर्जी तरीके से जमीन खरीद के मामले में जेल जा चुका है। इसके बावजूद वह सिंडिकेट चलाकर मोहला में अवैध प्लाटिंग कर रहा है।

पटवारी से लेकर रजिस्ट्री तक सब शामिल

आसान नामांतरणः अवैध प्लाटिंग के भूखंडों की रजिस्ट्री के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा बड़ी आसानी से नामांतरण कर दिया जा रहा है, जबकि अधिकारी जानते हैं कि यह उपखंड अवैध है।

पटवारी काट रहे नक्शाः नामांतरण के बाद हल्का पटवारी मूल खसरा से उपखंडों का नक्शा काट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पटवारी भू-माफियाओं के साथ मिलकर मोटी कमाई कर रहे हैं।

खरीददारों से धोखाः कॉलोनाइजर लोगों को बिजली, नाली, गार्डन जैसी सुविधाओं का लालच देकर जमीन बेच रहे हैं। मौके पर सिर्फ मुरम डालकर कच्चा सड़क बना है। अन्य कोई सुविधा नहीं है।

राजस्व विभाग की भूमिका संदिग्ध : सूत्रों के अनुसार मोहला जिले में एक भी वैध कॉलोनाइजर पंजीकृत नहीं है और न ही कोई प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना अनुमति के इतने बड़े पैमाने पर कॉलोनियां कैसे बस रही हैं ?

प्रशासन का बयान : इस संबंध में तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा ने कहा कि "अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है। रजिस्ट्री और नामांतरण न हो इसके लिए लेटर जारी कर दिया गया है। संबंधित पटवारी से जानकारी ली जाएगी कि मोहला में कितनी अवैध प्लाटिंग हुई हैं।"

अब देखना होगा कि खबर प्रकाशन के बाद राजस्व विभाग इस अवैध कारोबार पर रोक लगाता है या भू-माफियाओं का गोरखधंधा ऐसे ही चलता रहेगा।

करण कुंद्रा पर पुराने आरोपों को लेकर सान्वी तलवार ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई अभिनेत्री सान्वी तलवार ने अपने करियर के एक दौर में निजी विवाद को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं। अब काफी समय बाद अभिनेत्री ने उस दौर को याद करते हुए अपनी सोच और उससे मिली सीख के बारे में बात की। सान्वी ने कहा कि किसी भी संवेदनशील मामले पर बोलने के लिए व्यक्ति का खुद मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को भी संदेश दिया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वे उस समय अपनी बात नहीं रख पाईं, तो बाद में भी अपनी आवाज उठा सकती हैं। दरअसल, सान्वी ने टीवी शो ये कहां आ गए हम में अभिनेता करण कुंद्रा के साथ काम किया था। इसी शो के दौरान उन्होंने करण कुंद्रा पर कथित तौर पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि काम के दौरान करण कुंद्रा ने कथित तौर पर उनकी सहमति के बिना उन्हें किस किया और थप्पड़ भी मारा। इस मामले में शो की निर्माता एकता कपूर ने हस्तक्षेप किया था और इसके बाद शो की निर्देशन टीम में बदलाव किए गए थे। अब इस मामले पर बात करते हुए सान्वी ने कहा कि उन्होंने जिंदगी से यह सीखा है कि अपनी बात उसी समय रखनी चाहिए, जब इंसान खुद को इसके लिए पूरी तरह तैयार महसूस करे। अभिनेत्री ने कहा, पहले मैं अपनी बात सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा करती थी, जिनके साथ बात करना मुझे जरूरी लगता था। जब कोई निजी बात कई लोगों तक पहुंचती है तो कई बार उसका मतलब बदल जाता है और कहानी अलग रूप ले लेती है। अब मैं अपनी बात खुलकर रखने में सहज महसूस करती हूं, क्योंकि यह मेरा खुद का फैसला है और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सान्वी ने कहा, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई बात सही है और उसे सामने रखना जरूरी है, तो उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए। हर किसी का अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने का तरीका अलग होता है। किसी पर भी यह दबाव नहीं होना चाहिए कि उसे किसी घटना के तुरंत बाद ही बोलना पड़े। सही समय वही होता है, जब व्यक्ति खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करे। जब सान्वी से पूछा कि उन्होंने इस मुद्दे पर इतने समय बाद बात क्यों की और उन महिलाओं के लिए उनका क्या संदेश है, जो अपने साथ हुए किसी गलत अनुभव के बारे में बोलने से डरती हैं, तो सान्वी ने कहा कि हर महिला को अपनी सुविधा और तैयारी के अनुसार फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है और वह उस समय अपनी बात नहीं रख पाई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब भी वह खुद को तैयार महसूस करे, उसे आगे आकर अपनी कहानी बतानी चाहिए। अगर लोग अपने अनुभवों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। अभिनेत्री ने महिलाओं को हिम्मत देते हुए कहा, अपनी बात रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए सही समय और सही मानसिक स्थिति का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज की अहमियत समझनी चाहिए और अपने अनुभवों को दबाकर नहीं रखना चाहिए।

करण जौहर फिर बने 'ट्रेटर्स 2' के होस्ट

फिल्ममेकर करण जौहर 'ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन के लिए होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं। सोमवार को मेकर्स ने शो का प्रोमो जारी किया। इस प्रोमो में करण जौहर का स्टाइलिश अंदाज फैंस को नजर आया। पिछले सीजन में इस शो को उन्होंने शानदार तरीके से होस्ट किया था।

'ट्रेटर्स' इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर रोमांचक रियलिटी फॉर्मेट का भारतीय रूपांतरण है। इसका दूसरा सीजन दर्शकों को इस बार भारत में हैरान करेगा। यह शो 13 अगस्त को प्राइम वीडियो पर आएगा। शो में कई बॉलीवुड सेलेब्स, इंफ्लुएंसर्स के शामिल होने की बात सामने आई है।

नए सीजन के बारे में बात करते हुए प्राइम वीडियो ओरिजनल, इंडिया के निदेशक और प्रमुख निखिल मधोक ने कहा, 'शो ट्रेटर्स के पहले सीजन को मिली प्रतिक्रिया ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया। यह प्राइम वीडियो इंडिया की सबसे खास रियलिटी फ्रेंचाइजी में से एक बन गया है, जिसने समझदारी भरे गेमप्ले, मनोवैज्ञानिक रणनीति और दिलचस्प मनोरंजन के अनूठे मिश्रण के साथ इस शैली को बदल दिया है। देश भर के दर्शक इसके भावनात्मक रूप से भरे माइंड गेम्स और बिना किसी फिल्टर वाले ड्रामे से जुड़ गए थे। दूसरे सीजन के साथ, दांव ऊंचे हैं, गेमप्ले और तेज हैं, ड्रामा और भी जबरदस्त है। खिलाड़ियों की नई लाइन-अप दर्शकों को हर मोड़ पर रोमांच से भर देगी। हम करण जौहर की होस्ट और मास्टर ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में वापसी से बहुत उत्साहित हैं।'

अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान संग काम करने की ख्वाहिश हैं

आज जाने-माने निर्देशक बन चुके अहमद खान के करियर का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। चाइल्ड आर्टिस्ट से कोरियोग्राफर बने और फिर इंडस्ट्री के तमाम बड़े स्टार्स को नचाने वाले अहमद खान इन दिनों चर्चा में हैं निर्देशक के रूप में अपनी ताजा-तरीन फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से। इस फिल्म में एक साथ 30-35 बड़े कलाकारों को हैंडल करने वाले अहमद खान अब तक अपने करियर में तकरीबन सभी बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं, मगर वो शेर है न- बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, तो इसी तर्ज पर इस खास बातचीत में वह न केवल अपने करियर के सफर पर बात करते हैं, बल्कि ट्रेजिडी किंग कहलाने वाले दिलीप कुमार, बादशाह खान और बिग बी से जुड़ी यादों को भी साझा करते हैं।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं, 'बच्चन साहब के साथ कोरियोग्राफर के रूप में काम कर चुका हूं। मगर मुझे इंतजार है एक अच्छी स्क्रिप्ट का। वैसे बिग बी इन दिनों चुनिंदा काम ही कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार हमारी प्लानिंग किस्मत के आगे फेल हो जाती है। अब जैसे मैं अपने निर्देशन की शुरुआत शाहरुख खान के साथ 'सब्र' नामक फिल्म से करना चाहता था, मगर उसी दौर में शाहरुख खान अपने प्रोडक्शन की मैं हूं न लेकर आए। उस समय शाहरुख ने कहा था कि पहले वह अपनी फिल्म करेंगे और उसके बाद मेरी। लेकिन उनकी फिल्म में देरी होती रही और मुझे भी अपना काम शुरू करना था, इसलिए मैंने अपनी फिल्म शुरू कर दी।'

अपनी हालिया फिल्म में सितारों के मेले के साथ काम करने वाले अहमद ने कलाकारों से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताईं। उन्हीं के शब्दों में, 'देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि सब मेरे दोस्त थे। किसी ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। सबसे पहले अक्षय कुमार समय से पहले सेट पर आ जाते थे। हम सबको पता था कि कोई न कोई अगर गड़बड़ करेगा तो शूटिंग प्रभावित होगी। इसलिए हर कोई यही सोचता था कि कहीं गलती मुझसे न हो जाए। उसी वजह से काम बहुत अच्छे से हुआ। हमारे सेट पर जॉनी लीवर, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे धुरंधर कॉमेडियन भी थे, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सेट पर कोई भी कलाकार इनसिक्योर नहीं था। उल्टा सब एक-दूसरे से कहते थे, 'तू कर ले... तू कर ले। इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई।'

समृद्धि शुक्ला ने रिश्तों में बराबरी पर रखी बात

मुंबई टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री समृद्धि शुक्ला इन दिनों अपने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा के किरदार को लेकर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ वह अपनी सोच और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बात रखने के लिए भी जानी जाती हैं। इस बीच उन्होंने घर-परिवार, शादी और रिश्तों में जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर अपनी राय साझा की है।

समृद्धि ने कहा कि आज के समय में भी कई महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां अकेले संभालें, जबकि परिवार चलाने की जिम्मेदारी पति-पत्नी दोनों की बराबर होनी चाहिए।

समृद्धि शुक्ला ने महिलाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं, जिनसे हर काम को संभालने की उम्मीद की जाती है। उनसे कहा जाता है कि वे बच्चों की देखभाल करें, अगर चाहें तो नौकरी करें और फिर घर लौटकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी निभाएं। कई बार महिलाएं खुद खाना नहीं बनातीं, फिर भी उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे घर की हर व्यवस्था पर नजर रखें, कुक से बात करें, घर के कामों को मैनेज करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे।

उन्होंने कहा, इस तरह की सोच को बदलने की जरूरत है। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वे मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों एक ही घर में रहते हैं, घर की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों की परवरिश में भी दोनों की बराबर भागीदारी होती है। ऐसे में यह सही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाए। समृद्धि ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और वह कुछ समय के लिए काम पर नहीं जा सकती, तो उस दौरान पति को आगे बढ़कर जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। वहीं, जब महिला दोबारा अपने करियर या सपनों की ओर लौटना चाहे, तो पति घर की जिम्मेदारियों में सहयोग कर सकता है।

रिश्ते में सबसे जरूरी चीज एक-दूसरे के सपनों को समझना और उनका सम्मान करना है।

अभिनेत्री ने कहा, परिवार का मतलब एक-दूसरे का साथ देना होता है, न कि पुराने नियमों के अनुसार महिला और पुरुष की भूमिकाएं तय कर देना।

किसी एक व्यक्ति से हमेशा त्याग करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। एक अच्छे रिश्ते में दोनों लोग एक-दूसरे के लिए जगह बनाते हैं और मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं।

भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं होती

अभिनेत्री सीरत कपूर ने अपनी अभिनय यात्रा में दक्षिण भारतीय सिनेमा के योगदान को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि साउथ इंडस्ट्री में काम करने के अनुभव ने उन्हें किरदारों को ज्यादा गहराई से समझना सिखाया है। जब एक कलाकार अलग-अलग जगहों और संस्कृतियों के बीच काम करता है, तो वह भावनाओं को समझने और उन्हें पर्दे पर उतारने का तरीका बेहतर तरीके से सीखता है।

दक्षिण भारतीय सिनेमा ने बदली उनकी सोच

लग-अलग भाषाओं में काम करना मेरे लिए एक चुनौती भी रहा और सीखने का बड़ा मौका भी। इस अनुभव ने मुझे अभिनय में ज्यादा सहज, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाला और अपने काम के प्रति ईमानदार बनाया। इसने मुझे सिखाया कि भावनाओं को शब्दों की जरूरत नहीं होती।'' अभिनेत्री ने आज के दौर में कलाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''किसी कलाकार के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसे सही कारणों से याद रखा जाए। लोकप्रियता और चर्चा कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन अच्छे काम से मिलने वाला सम्मान लंबे समय तक बना रहता है।'' सीरत कपूर जल्द ही फिल्म 'जटस्या मरणम ध्रुवम' में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ दिग्गज अभिनेता जेडी चक्रवर्ती भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे।

यह फिल्म अगले महीने पांच भाषाओं में रिलीज होने वाली है। हाल ही में सीरत ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक मुश्किल अनुभव को भी साझा किया था। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म के आखिरी क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। उस सीन के लिए उन्होंने चूड़ियां पहनी थीं, लेकिन शूट पूरा होने के बाद हाथों में सूजन आने की वजह से उन्हें निकालना मुश्किल हो गया था। अपने इस अनुभव को याद करते हुए सीरत ने कहा, 'मुझे याद है जब हम फिल्म के आखिरी क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग कर रहे थे। मैंने उस सीन के लिए चूड़ियां पहनी थीं और शूट पूरा होने के बाद सूजे हुए हाथों की वजह से हम उन्हें निकाल नहीं पाए। टीम की मदद से जैसे-तैसे चूड़ियां निकाली गईं।'

ऋषभ शेट्टी की फिल्म में अहम किरदार निभाएंगी भूमि पेडनेकर

साल 2022 में 'कांतारा' और 2025 में 'कांतारा चैप्टर 1' से तहलका मचाने वाले दक्षिण भारतीय अभिनेमा ऋषभ शेट्टी अपनी अगली फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' के नाम से रिलीज होने वाली इस फिल्म में ऋषभ, शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। अब इस फिल्म से जुड़ एक नया अपडेट सामने आया है। फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रसे भूमि पेडनेकर की भी एंट्री हो गई है। फिल्म में भूमि पेडनेकर वॉरियर क्वीन बेलवाडी मल्लम्मा का किरदार निभाएंगी। मल्लम्मा एक निडर योद्धा रानी थीं, जिन्हें उनकी बहादुरी और अटूट जज्बे के लिए याद किया जाता है। बेलवाड़ी मल्लम्मा ने देश की पहली महिला सैनिक टुकड़ी का गठन किया था। ऐसा करने वाली वह पहली रानी थीं। कहा जाता है कि वो अपने चार माह के बेटे को गोद में लेकर शिवाजी महाराज की सेना से युद्ध लड़ी थीं।

सतकर्ता, समय पर जांच और टीकाकरण से हेपेटाइटिस की रोकथाम संभव –डॉ. लोकेश साहू

बरसात के मौसम में दूषित भोजन और पानी के कारण बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा, व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षित जीवनशैली ही संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश एवं सीएमएचओ डॉ अमृत लाल रोहलेडर के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय बेमेतरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हेपेटाइटिस की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार और टीकाकरण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और हितग्राहियों का हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. लोकेश साहू ने की।

इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम हेपेटाइटिसः आओ इसे खत्म करें के अनुरूप विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर जांच, सुरक्षित व्यवहार और टीकाकरण से हेपेटाइटिस संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

डॉ. लोकेश साहू ने कहा कि बरसात के मौसम में दूषित भोजन और पानी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने नागरिकों से फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह धोकर उपयोग करने, स्वच्छ पानी पीने, भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाने तथा खुले एवं दूषित खाद्य पदार्थों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षित जीवनशैली ही संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों ने बताया कि हेपेटाइटिस-बी के प्रमुख लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते, भूख कम लगना, अत्यधिक थकान, जोड़ों में दर्द एवं अवसाद शामिल हैं, जबकि हेपेटाइटिस-सी में लगातार थकान, अनिद्रा, पैरों में सूजन, त्वचा में खुजली तथा गहरे रंग का मूत्र जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए।

कार्यक्रम में बचाव के लिए सुरक्षित रक्त का उपयोग, एक बार उपयोग होने वाले रेजर ब्लेड एवं इंजेक्शन का प्रयोग, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं साझा न करने, असुरक्षित यौन संबंधों से बचने तथा घावों को सुरक्षित ढंककर रखने की सलाह दी गई। साथ ही नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद निर्धारित समय में हेपेटाइटिस-बी का टीका लगाने, सभी गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस-बी जांच कराने तथा संक्रमित माता से जन्म लेने वाले शिशुओं को आवश्यक इम्यूनोग्लोब्युलिन एवं टीकाकरण कराने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, कमर्चारियों, एएनएम, मितानिनों एवं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस के साथ-साथ मौसमी बीमारियों की रोकथाम, उपचार और जनजागरूकता संबंधी जानकारी भी दी गई। जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों को स्वच्छता, सुरक्षित खान-पान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. शरद कोहाड़े, जिला नोडल अधिकारी डॉ. अस्मिता श्रीवास्तव, मेडिसिन विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ के साथ चिकित्सालय अधिकारी, अस्पताल प्रबंधक डॉ. स्वाति यदु, लैब इंचार्ज श्रीमती गीतांजलि बेहरा, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कमर्चारी उपस्थित रहे।

खास खबर

शहरी क्षेत्र की आवासीय व डायवर्टेड भूमि का एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, विलंब न करें – जिला प्रशासन

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिला प्रशासन बेमेतरा ने जिले के समस्त शहरी क्षेत्र के भूमि स्वामियों से अपील की है कि वे अपनी आवासीय एवं डायवर्टेड भूमि का एग्रीस्टैक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन भूमि स्वामियों की जानकारी एग्रीस्टैक पोर्टल पर अनक्लेम श्रेणी में प्रदर्शित हो रही है, वे बिना विलंब अपना क्लेम प्रस्तुत कर पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि उनकी भूमि का रिकॉर्ड शासन के डिजिटल डेटाबेस में सही एवं प्रमाणित रूप से दर्ज हो सके।

जिला प्रशासन ने बताया कि एग्रीस्टैक भारत सरकार एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से भूमि संबंधी अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। भविष्य में शासन द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं, प्रमाण-पत्रों, भूमि संबंधी सुविधाओं तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत एवं सत्यापित होना आवश्यक होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की असुविधा, विलंब अथवा तकनीकी समस्या से बचने के लिए सभी पात्र भूमि स्वामी समय रहते अपना पंजीयन एवं क्लेम अवश्य पूर्ण कर लें। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि वर्तमान में अनेक भूमि स्वामियों के खाते अनक्लेम श्रेणी में लंबित हैं। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा क्लेम प्रस्तुत किए बिना भूमि का सत्यापन पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी संबंधित नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें और अपने भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप से प्रमाणित कराएं।

भूमि स्वामी अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र, संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित एग्रीस्टैक पंजीयन एवं क्लेम की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम समय की प्रतीक्षा न करें तथा समय पर पंजीयन कराकर भविष्य में मिलने वाली शासकीय सुविधाओं एवं ऑनलाइन सेवाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए संबंधित तहसील कार्यालय, राजस्व निरीक्षक, पटवारी अथवा निकटस्थ लोक सेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

85 की उम्र में भी स्वच्छता का जज्बा कायम, तिरिथ राम बना रहे गांव को प्लास्टिक मुक्त

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने में उम्र कोई बाधा नहीं है। विकासखंड कवर्धा की ग्राम पंचायत धरमपुरा के 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक तिरिथ राम साहू इसका जीवंत उदाहरण हैं। जीवन के इस पड़ाव में भी वे पूरे उत्साह और समर्पण के साथ गांव को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं।

पिछले छह माह से श्री साहू प्रतिदिन सुबह गांव की गलियों की सफाई, प्लास्टिक कचरा संग्रहण तथा नालियों की सफाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही वे ग्रामीणों को खुले में कचरा नहीं फेंकने, गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। तिरिथ राम साहू घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। कचरा संग्रहण के दौरान स्वच्छाग्रही दीदियों के साथ ग्रामीणों को सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं तथा गांव में एकत्रित प्लास्टिक कचरे को संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने में भी सक्रिय रहते हैं। स्वयं हमेशा कपड़े का थैला उपयोग कर वे दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने तिरिथ राम साहू के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यही है असली जनभागीदारी। स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा, जब समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी होगी। तिरिथ राम साहू जैसे नागरिक पूरे जिले के लिए प्रेरणा हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि तिरिथ राम साहू यह साबित करते हैं कि यदि सेवा का जज्बा हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। स्वच्छता के लिए उनका समर्पण युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी है। ऐसे नागरिक वास्तव में स्वच्छता अभियान के ब्रांड एंबेसडर हैं। जिला समन्वयक संजय सोनी ने बताया कि दादा जी के समझाने के तरीके से गांव में प्लास्टिक के उपयोग में लगभग 90 प्रतिशत तक कमी आई है।

अमित खण्डेलवाल को उल्लेखनीय कार्यों के लिए रीजन चेयरमेन की सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

लायंस क्लब की बड़ी उपलब्धि, अध्यक्ष अमित खण्डेलवाल हुए सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव के लिए गर्व का क्षण उस समय आया जब लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी के अध्यक्ष लायन अमित खण्डेलवाल को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और उल्लेखनीय कार्यों के लिए रीजन चेयरमेन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी को वर्ष 2025-26 का इंटरनेशनल एक्सीलेंट क्लब अवार्ड भी प्रदान किया गया। अध्यक्ष अमित खण्डेलवाल के कार्यकाल की यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे पूरे राजनांदगांव का गौरव बढ़ा है।

रायपुर स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में आयोजित इंटरनेशनल लायंस क्लब के भव्य इंस्टॉलेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह तथा प्रथम कैबिनेट मीटिंग में लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कार्यक्रम में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लायन ए.पी. सिंह ने क्लब के अध्यक्ष लायन अमित खण्डेलवाल को इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल मैडल पहनाकर सम्मानित किया जो की पूरे 145 क्लब में सिर्फ अध्यक्ष अमित खण्डेलवाल को यह मैडल का सम्मान प्राप्त हुआ है तथा उन्हें रीजन चेयरमेन पद की शपथ दिलाई।

समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि लायन ए पी सिंग, लायन विनोद लाड़िया कुलभूषण पवन मित्तल, जे पी सिंग, जी एस होरा, राजू मनवानी, संगीता जटिया, प. वीण वशिष्ठ, गवर्नर रिपुदमन सिंह पुसरी, विजय अग्रवाल मलिक, अनिल अग्रवाल, यह सम्मान उन्हें वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक 33 नए सदस्यों को क्लब से जोड़ने तथा पूरे डिस्ट्रिक्ट में 105 सदस्यों के साथ सबसे बड़ा क्लब बनाने की उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया। इसके साथ ही लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एक्सीलेंट क्लब अवार्ड 2025-26 से भी नवाजा गया। रीजन चेयरमेन के रूप में अमित खण्डेलवाल के नेतृत्व में 3 जोन चेयरपर्सन कार्य करेंगे तथा उनके अधीन 10 क्लब शामिल रहेंगे, जिनमें भिलाई के 7 क्लब, राजनांदगांव के 2 क्लब और अहिवारा का 1 क्लब शामिल है। यह जिम्मेदारी उनके नेतृत्व कौशल और संगठन के प्रति समर्पण का प्रमाण मानी जा रही है।

क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि अध्यक्ष लायन अमित खण्डेलवाल के नेतृत्व में मिली यह सफलता पूरे लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी की टीम की मेहनत, सेवा भावना और संगठनात्मक एकजुटता का परिणाम है। एक्सीलेंट क्लब अवार्ड तथा रीजन चेयरमेन की जिम्मेदारी मिलना क्लब के इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है। इससे न केवल क्लब की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि पूरे राजनांदगांव का नाम भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। कार्यक्रम के अंत में लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं पूरी टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं।

इस अवसर पर पद्मश्री लायन डॉ. पुखराज बाफना, लायन टीना खण्डेलवाल, डिस्ट्रिक्ट माइक्रो चेयरपर्सन लायन राजकुमार शर्मा, लायन शोभा शर्मा, लायन राजेश जैन (राजू), क्लब अध्यक्ष लायन दीपक जैन (नवलखा), सचिव लायन अशोक पवार, जोन चेयरपर्सन लायन तरणदीप अरोरा सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। रीजन चेयरमैन बनने पर अध्यक्ष लायन दीपक जैन (नवलखा), लायन सचिव अशोक पवार, कोषाध्यक्ष लायन मुकेश शर्मा, लायन तरणदीप अरोरा, लायन बृजकिशोर सुरजन, पद्मश्री लायन डॉ. पुखराज बाफ्ना, उमेद कोठारी, संतोष लोहिया, माइक्रो चेयरपर्सन राजकुमार शर्मा, लायन कमल किशोर साहू, लायन मयंक शर्मा, लायन विजय कोटड़िया, लायन चंद्रिका प्रसाद सिन्हा, लायन भावेश अग्रवाल, लायन नेहागुप्ता, लायन श्यामचरण गुप्ता, लायन प्रकाश सांखला, राजेश जैन (राजू), लायन सुरेश शर्मा, सुदामा मोटलानी, रमेश गुप्ता, मुकेश चौबे, शोभा चौरसिया, कंचन चौबे सहित बड़ी संख्या में लायन सदस्यों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

क्लब के संरक्षक लायन बलदेव सिंह भाटिया, लायन बहादुर अली, लायन बृजकिशोर सूरजन, लायन शारदा तिवारी, लायन सुशील पसारी, लायन अशोक चौधरी एवं लायन नंदकुमार अग्रवाल ने इस उपलब्धि को पूरे क्लब और राजनांदगांव के लिए गौरवपूर्ण बताया।

एक दिन की बारिश ने खोल दी सरकारी व्यवस्थाओं की पोल

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

बेमेतरा जिले के पेण्ड्रीतराई स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गई। स्कूल परिसर में जलभराव होने से बच्चों को पानी के बीच से स्कूल आने-जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल—जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं, तो बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?

बेमेतरा जिले के ग्राम पेण्ड्रीतराई स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में महज एक दिन की बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर पूरे परिसर तक पानी भर जाने के कारण छात्र-छात्राओं को जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है।

बरसात के इस मौसम में जलभराव के कारण फिसलने, चोट लगने और सांप-बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी बना हुआ है। इसके बावजूद अब तक जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और प्रशासन केवल आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं।

सरकार शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?

बिरला ओपन माइंड स्कूल में पुलिस की रक्षा टीम ने बच्चों को सिखाए सुरक्षा के गुर

गुड टच-बैड टच, आत्मरक्षा और अभिव्यक्ति ऐप की दी जानकारी, 50 से अधिक छात्र-शिक्षक हुए शामिल

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव पुलिस की रक्षा टीम ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से बुधवार को बिरला ओपन माइंड स्कूल, अनुपम नगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा टीम प्रभारी उप निरीक्षक शारदा बंजारे, महिला आरक्षक कौशिल्या साहू और आरक्षक रेणु मेश्राम ने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा टिप्स दिए।

क्या-क्या सिखाया गया

गुड टच – बैड टच की पहचान और उससे बचाव के उपाय। आत्मरक्षा के बुनियादी तरीके और व्यक्तिगत सुरक्षा के नियम। अनजान व्यक्तियों के साथ न जाने और किसी भी अजनबी से खाने-पीने की वस्तु स्वीकार न करने की समझाइश। किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में तुरंत माता-पिता, शिक्षक या पुलिस को सूचना देने के निर्देश

अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया गया

कार्यक्रम के दौरान रक्षा टीम ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को 'अभिव्यक्ति ऐप' के बारे में जानकारी दी और मोबाइल में डाउनलोड भी कराया। टीम ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में यह ऐप सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थी एवं शिक्षक सहित 50 से अधिक लोग उपस्थित रहे। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पुलिस के इस जागरूकता अभियान की सराहना की। स्कूल प्रशासन ने भी राजनांदगांव पुलिस के इस प्रयास को सराहनीय बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया।

समीक्षा बैठक | शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे व विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी

जल संरक्षण, पीए आवास, स्वच्छ भारत मिशन व निर्माण कार्यों में समयबद्ध प्रगति के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्ता एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे तथा विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने वॉटर बॉडी रिचार्ज, रिचार्ज पिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेंच निर्माण, पौधरोपण एवं अन्य जल संरक्षण संबंधी कार्यों को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संरक्षण सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी जल संरचनाओं का निर्माण किया जाए, जिससे भू-जल स्तर में वृद्धि हो और भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने वर्ष 2016 से 2023 तक स्वीकृत ऐसे अपूर्ण आवास, जिनका निर्माण संभव नहीं है, उन्हें नियमानुसार निरस्त करते हुए संबंधित हितग्राहियों से वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं वर्ष 2024 से 2026 तक स्वीकृत अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों ने अभी तक आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उनके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से नियमित पेशी कराते हुए आवश्यक वसूली एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी हितग्राहियों को अपने आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना अनिवार्य रूप से बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि प्रत्येक आवास जल संरक्षण का भी मॉडल बन सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भुगतान हेतु पात्र सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र परीक्षण उपरांत जिला कार्यालय भेजा जाए, जिससे हितग्राहियों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जनपद पंचायतों को इस कार्य में विशेष गंभीरता एवं तत्परता बरतने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीओ) एवं उप अभियंताओं (सब इंजीनियर्स) को नियमित मैदानी निरीक्षण करने, कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा प्रगति में लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कार्यपालन अभियंता, सभी अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा सेतु व सीएससी संचालकों को सैंड बैक और रिजेक्शन कम करने के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सेवा सेतु एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि सेवा सेतु एवं सीएससी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों में सैंड बैक एवं रिजेक्शन को कम करने, अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत करने तथा गलत दस्तावेज को स्कैन नहीं करने के निर्देश दिए। सभी सीएससी संचालक आवेदन करते समय आवश्यक एवं अनिवार्य दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें तथा उन्हीं के आधार पर आवेदन प्रस्तुत करें।

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव : नारायण कन्नौजे बने अध्यक्ष, 205 वोटों से दर्ज की अपनी जीत

संतोष रजक सचिव, सुषमा चौहान बनीं कोषाध्यक्ष, दोपहर से ही तय थी नतीजे की तस्वीर

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव के चुनाव का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और धीमी-धीमी बरसात के बीच सुबह से शाम तक चली मतगणना के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कन्नौजे संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। दोपहर से ही मतगणना में मिली बढ़त से यह स्पष्ट हो गया था कि अध्यक्ष पद पर वे ही बाजी मारेंगे।

579 अधिवक्ताओं ने किया मतदान

चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला मुख्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुल 655 मतदाताओं में से 579 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। परिणाम घोषित होते ही परिसर में जश्न का माहौल बन गया। समथर्कों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण कन्नौजे और अन्य पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं की विशेष उपस्थिति रही। नए कार्यकारिणी के गठन के साथ ही अधिवक्ताओं को अधिवक्ता हित और न्यायिक सुविधाओं को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।

प्रमुख पदों के चुनाव परिणाम

अध्यक्ष पदः
नारायण कन्नौजे - 351 वोट से विजयी हुए हैं
आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव - 146 वोट

सचिव पदः
संतोष रजक - 353 वोट से विजयी
रवि कुमार बुधनी - 140 वोट

सहसचिव पदः
महेन्द्र सिंह ठाकुर - 371 वोट से विजयी
पंकज कुमार गुप्ता - 185 वोट

कोषाध्यक्ष पदः
सुषमा चौहान - 366 वोट से विजयी
स्मिता गुप्ता - 189 वोट

उपाध्यक्ष पुरुषः
अमिताप कुमार श्रीवास्तव - 178 वोट से विजयी
विनोद कुमार ठाकुर - 174 वोट

उपाध्यक्ष महिलाः
जया श्रीवास्तव - 294 वोट से विजयी
बीना साहू - 265 वोट

कार्यकारिणी सदस्य - 04 पदः
संजीव श्रीवास्तव - 353 वोट
गुरु शंकर नेताम - 346 वोट
सुरेन्द्र सिंह ठाकुर - 339 वोट
नरेश गंजीर - 313 वोट

गुरु पूणिर्मा पर खारून दाई की महाआरती में शामिल हुए जोहार छग पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-रायपुर

गुरु पूणिर्मा के पावन अवसर पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल गुरुवार को खारून नदी के तट पर पहुंचकर महाआरती में शामिल हुए। जेल से रिहाई के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक धार्मिक उपस्थिति थी। उन्होंने रायपुर और दुर्ग की सीमा पर स्थित खारून दाई के तट पर सपरिवार पूजा-अचर्ना की और छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि एवं शांति के लिए आशीर्वाद मांगा।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद

आरती में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के रायपुर और दुर्ग जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। पार्टी के सेनानियों ने खारून दाई के जयकारे लगाए। कार्यक्रम को देखते हुए एहतियातन अमलेश्वर थाना बल घाट पर तैनात रहा।

परंपरा से जुड़ी आरती

ज्ञात हो कि महादेव घाट पर कुछ बाहरी लोगों द्वारा स्थायी पाटा लगाकर आरती के नाम पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा नगर निगम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया गया था। हटकेश्वर महादेव मंदिर के सेवादार गिरी महाराज 11 पीढ़ियों से खारून नदी की आरती करते आ रहे हैं। अब उनके पुत्र 12वीं पीढ़ी के रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आरती के बाद प्रदेशभर में शांति और समृद्धि की कामना की गई।

जन्मदिन पर पोस्टर नहीं, पेड़ लगाओ - विधायक रिकेश

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपने जन्मदिन को लेकर समथर्कों से अनूठी अपील की है। उन्होंने 10 अगस्त को पोस्टर लगाने के बजाय पेड़ लगाने की प्रतिस्पर्धा करने की बात कही है। विधायक ने कहा कि जन्मदिन पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पोस्टर लगाते हैं। उन्होंने इस बार ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं करने की अपील की है। इसके बजाय अधिक से अधिक पौधे लगाने की बात कही है।

सरकारी पोल पर पोस्टर लगाने से भी किया इनकार : रिकेश सेन ने नगर निगम के सरकारी पोल पर पोस्टर लगाने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई समर्थक सरकारी पोल पर उनका पोस्टर लगाता है, तो उसे तत्काल हटाया जाए। उनका कहना है कि जन्मदिन पर पोस्टर लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण है। पौधे लगाने से शहर को हरियाली मिलेगी और पर्यावरण भी बेहतर होगा।

जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की पहल : विधायक की अपील में जन्मदिन को सामाजिक और पर्यावरणीय अभियान से जोड़ने का संदेश दिया गया है। उन्होंने समथर्कों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य जन्मदिन के उत्सव को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक पोस्टर लगाने से भी बचने का संदेश दिया गया है।

पोस्टर की जगह पौधा बने जन्मदिन का उपहार : विधायक की अपील का संदेश साफ है। जन्मदिन पर पोस्टर लगाने के बजाय पौधा लगाया जाए। यदि समर्थक इस अपील को अभियान का रूप देते हैं, तो जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में पौधरोपण हो सकता है।

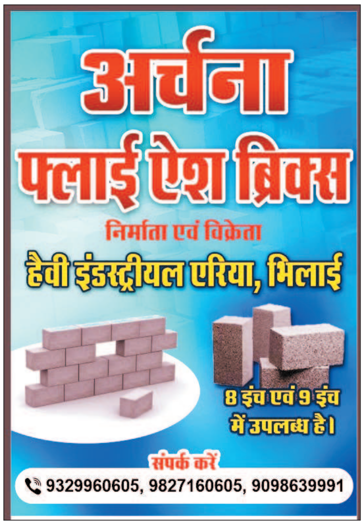

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100